



04 - अमेरिका-ईरान : केवल युद्धविरोध पर्याप्त नहीं



05 - बदलते दौर में उत्पादकता का बढ़ता महत्व



06 - पाखंड जिससे लड़ नहीं सका



07 - समस्याओं का हुआ ऑन-द-स्पॉट समाधान, खुशी...

कृष्ण

प्रसंगवश

नेहरू और मोदी के बाद अब बना नया 'नीतीश कुमार आर्काइव'

कृष्ण मुरारी

नीतीश कुमार को 'सुशासन बाबू' के रूप में पहचान मिलने से बहुत पहले या फिर राजनीतिक पाला बदलने के कारण आलोचकों द्वारा 'पलटू राम' कहे जाने से पहले-वह पटना की सड़कों पर नारे लगाने वाले जेपी आंदोलन के एक युवा कार्यकर्ता थे। बिहार के 75 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक जीवन की वह जोशीली शुरुआत लगभग लोगों की यादों से गायब हो चुकी थी, लेकिन अब उसे फिर से सामने लाने की एक डिजिटल कोशिश शुरू हुई है।

Nitish Archive नाम की एक नई वेबसाइट उन भूले-बिसरे वर्षों को खोजकर सामने ला रही है, ताकि बिहार की राजनीतिक यादों को डिजिटल रूप में संजोया जा सके। यह परियोजना पिछले महीने एक फेसबुक पेज के रूप में शुरू हुई थी। इसमें नीतीश कुमार के संसद में दिए गए दुर्लभ भाषण, 1990 के दशक की अखबारों की कतरनें और उनके पुराने दोस्तों के इंटरव्यू साझा किए जा रहे हैं। उनके राजनीतिक जीवन के हर दौर को इसमें जगह दी जा रही है-समता पार्टी के दिनों से लेकर केंद्रीय रेल मंत्री के कार्यकाल और कई बार मुख्यमंत्री रहने तक। नीतीश आर्काइव के संस्थापक संजीव कुमार ने कहा, 'नीतीश भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जेपी आंदोलन के उनके लगभग सभी साथी अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। इसलिए हमने तय किया कि उनके करीब रहे लोगों की नज़र से नीतीश कुमार का दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया जाए।'

संजीव कुमार पटना के एक शोधकर्ता हैं और 'जातिगत जनगणना: सब हैं राजी, फिर क्यों बयानबाजी' नामक किताब के लेखक भी हैं, जो बिहार

की जाति जनगणना पर आधारित है। नीतीश आर्काइव अब राजनीतिक नेताओं को समर्पित गैर-आधिकारिक ऑनलाइन संग्रहालयों और श्रद्धांजलि मंचों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है। इनमें कुछ लोकप्रिय फैन पेज एक्स और इंस्टाग्राम पर चलते हैं, जैसे Nehruvian और Modi Archive, जबकि कुछ परिवारों, राजनीतिक दलों या संस्थानों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

नवंबर 2025 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने Nehru Archive शुरू किया था। यह एक मुफ्त और पूरी तरह खोजी जा सकने वाली डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें नेहरू की Selected Works के सभी 100 खंड मौजूद हैं। इस परियोजना का नेतृत्व कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया था, जो फंड के ट्रस्टी भी हैं। इसके अलावा चरण सिंह आर्काइव भी है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था और इसे पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हर्ष सिंह लोहित संचालित करते हैं।

हालांकि, 17 मई को जद(यू) के एक नेता ने नीतीश आर्काइव का औपचारिक शुभारंभ किया था, लेकिन यह एक स्वतंत्र परियोजना है और केवल प्रशंसा करने वाला मंच नहीं है। कई राजनीतिक फैन पेजों के विपरीत, जो सिर्फ टिप्पणी या तारीफ पर केंद्रित होते हैं, नीतीश आर्काइव बिहार के राजनीतिक इतिहास के अलग-अलग दौरों का एक संग्रह बनने की कोशिश करता है।

संजीव कुमार, जो तीन-चार शोधकर्ताओं की टीम के साथ इस मंच को चलाते हैं, कहते हैं, 'विरलेपण या राय देने के बजाय नीतीश आर्काइव पुरानी रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों को खुद बोलने देता है। ऐसा करके यह इस बात पर चर्चा शुरू करता है कि पिछले तीन दशकों में बिहार और उसके सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री

रहे नेता में कितना बदलाव आया है।'

एक महीने से भी कम समय में इस फेसबुक पेज के 20,000 फॉलोअर हो चुके हैं। यह परियोजना इंस्टाग्राम पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हाल ही में इस हैडल ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक पीएचडी शोधार्थी का संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने बिहार की जाति और राजनीति पर अपने शोध के लिए इस सामग्री को 'बेहद मूल्यवान' बताया।

जेन-जी पीढ़ी के लिए, जो नीतीश कुमार को सिर्फ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जानती है, यह आर्काइव राज्य की राजनीति का एक पुराना पारिवारिक एल्बम जैसा है, जिसे फिर से साफ करके लोगों के सामने लाया गया है। इसमें 1990 के दशक के राजनीतिक अभियानों की तस्वीरें, संसद में दिए गए भाषणों के अंश, समाजवादी राजनीति के अंदरूनी संघर्षों की कहानियाँ और उन दोस्तों के किस्से शामिल हैं, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले से जानते थे। जून के पहले हफ्ते में आर्काइव टीम के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर का अपना पहला दौरा किया। वहाँ दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ही नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी की स्थापना की थी। उस कार्यक्रम में नीतीश के पुराने कई सहयोगी भी मौजूद थे।

संजीव कुमार ने कहा, 'बाद के वर्षों में नीतीश और फर्नांडिस के रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। उन बुजुर्ग लोगों की यादों को दर्ज करने से नीतीश के बारे में एक नया नज़रिया सामने आया।' आर्काइव की पोस्टों में नीतीश कुमार के रेल मंत्री के कार्यकाल, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनकी राजनीतिक साझेदारी और 1990 के दशक में बिहार में समता पार्टी के विस्तार की अंदरूनी

कहानियाँ भी शामिल हैं।

यह आर्काइव कई स्रोतों से सामग्री जुटाता है-अखबारों की रिपोर्ट, संसद और विधानसभा के रिकॉर्ड, निजी संग्रह और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों की मौखिक यादें जिन्होंने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से ज्यादा यादों को दर्ज करना है।

कुमार ने कहा, 'कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरा उद्देश्य इन कहानियों को बहुत देर होने से पहले रिकॉर्ड करना है।' ऐसी ही एक याद बरिष्ठ राजनेता सरयू राय से जुड़ी है, जो 1960 के दशक के मध्य में पटना साइंस कॉलेज में नीतीश कुमार के साथ पढ़ते थे। बाद में दोनों की राजनीतिक राहें अलग हो गईं।

कभी-कभी पुरानी राजनीतिक विवादित बातें भी फिर से सामने लाई जाती हैं। एक पोस्ट में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कार्यकाल की उस चर्चा को दोबारा उठया गया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से पटना तक उनकी विशेष ट्रेन यात्राओं पर हर बार लगभग 5 लाख रुपये खर्च होते थे।

एक अन्य पोस्ट में संसद में बोलते हुए नीतीश कुमार 1990 के दशक की भारतीय राजनीति के एक बड़े विभाजन को बयान करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा था, 'हिंदुस्तान में दो तरह के हिंदू हैं। एक मंडल और दूसरा कर्मडल।' संजीव कहते हैं कि शुरू से ही उनकी इच्छा थी कि यह पहल किसी राजनीतिक दल की आधिकारिक परियोजना न बने, बल्कि स्वतंत्र बनी रहे। वह सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित नहीं रहना चाहते।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मानसून में देरी

बढ़ा 'बारिश' का इंतजार

● एक साथ 5 सिस्टम रोक रहे मानसून को ● अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही



लंबे समय तक सूखा और असमान बारिश के संकेत

अल नीनो की परिस्थितियाँ भी बन रही हैं। इससे लंबे समय तक सूखा और असमान बारिश देखने को मिल सकती है। उपग्रह के आंकड़े पूर्वी भारत में सक्रिय गरज-चमक का संकेत देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी भारत में बादलों का घनापन कम है। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार लंबा हो रहा है। 15-16 जून तक मानसून प्रदेश में एंटर हो जाता है, लेकिन इस बार यह 9 से 10 दिन लेट यानी, 25 जून तक एंटी कर सकता है। मानसून के लेट होने से जून की सामान्य बारिश के आंकड़े में गिरावट आई है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक, प्रदेश में 1 जून से अब तक 39 फीसदी पानी कम गिरा है। राजस्थान में गुरुवार से बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू समेत प्रदेश के 30 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर में 3 इंच बारिश हुई। वहीं, दो दिन राहत के बाद दिन का तापमान फिर से 40 डिग्री के ऊपर पहुँच गया है। यूपी में मानसून की चाल धीमी पड़ गई है। पिछले 5 दिनों से यूपी-बिहार बॉर्डर पर महराजगंज जिले के पास अटका हुआ है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुँच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे ये राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। 7 में 60 फीसदी तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग-अलग सिस्टम ऐक्टिव होना है। जैसे अरब सागर से तेज नमी वाली हवाएँ नहीं आ रही और दक्षिण से बादल उतर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। 1 से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 38 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की रही, जहाँ सामान्य से 78 फीसदी कम बारिश हुई। इसके बाद गुजरात में 79 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी-मानसून बारिश हो रही है। इसके बावजूद यूपी-राजस्थान समेत 7 राज्यों में तापमान 40 के पार है। अमरीकी मौसम विभाग ने उपग्रह के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

भारत ने खोज लिया ड्रैगन को काबू में रखने वाला ताला

● ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के इरादे मजबूत

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 2021 में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यह लोकेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जहाजी और नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। खासतौर पर पूर्वी हिंद महासागर और भारत की इंडो-पैसिफिक में भूमिका बढ़ाने के लिहाज से यह प्रोजेक्ट अहम माना जा रहा है। वह भी तब जब चीन इस पूरे समुद्री इलाके में अपने पांव पसार रहा है। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक बार फिर लेट लिखा है।



जयराम रमेश ने पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया- कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट के बारे में पत्र लिखा। उन्होंने इसमें पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि इस प्रोजेक्ट के अंदाज-अलग फंडों का पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आंकलन साफ तौर पर अपर्याप्त है। पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने यादव को लिखे अपने नए पत्र में कहा, 3 जून 2026 को मेरे पत्र के जवाब में 13 जून 2026 को आपका जो भी जवाब मिला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

subhasaverenews@gmail.com
facebook.com/subhasaverenews
www.subhasavere.news
twitter.com/subhasaverenews

सुप्रभात

जीवन एक फूल है उसकी सुगंध लेते रहो

जीवन एक वृक्ष है उसे आकाश छूने दो

जीवन एक नदी है उसे सबकी घास बुझाने दो

जीवन एक रास्ता है उस पर निरंतर चलते रहो

जीवन एक प्रकाश है उसे कभी अस्त होने मत दो।

-दुर्गाप्रसाद झाला

मित्र नरेंद्र, आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई

● मैक्रों ने हिंदी में कहा-भारत-फ्रांस की दोस्ती अमर रहे ● पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे, कहा-यह यात्रा बेहद व्यापक रही

पेरिस/नई दिल्ली (एजेंसी)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदी में वीडियो मैसेज शेयर किया है। उन्होंने कहा- प्रिय मित्र नरेंद्र, आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौर में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। इसके बाद मुस्कुराते हुए मैक्रों ने कहा, 'मुझे उम्मीद है यह (हिंदी संदेश) सही होगा। डिग्र प्राइम मिनिस्टर इस दोस्ती के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगली फरवरी (भारत यात्रा) आपसे मिलूंगा।' वहीं, फ्रांस से रवाना होने के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा- यह यात्रा सहभागिता और उपलब्धियों दोनों के लिहाज से व्यापक रही। दरअसल, पीएम मोदी 6 दिन का फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा पूरा



करके शुक्रवार सुबह भारत पहुंच चुके हैं। लोकतंत्र की ताकत, चायवाला पीएम बना- आज में ऐसे समय में फ्रांस आया हूँ, जब कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टनरशिप के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, जिसने एक चायवाले को यहाँ तक पहुँचा दिया। बीते 12 साल 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। भारत की जीडीपी दोगुना हुई है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। यूनिवर्सिटी की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड तीन गुना बढ़ गई है। मैं आपको कुछ और फैक्ट्स दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आज भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।

महिलाएं-किसान टेक्नोलॉजी से सशक्त - एक समय था, जब दूरदराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल था। आज उन्हीं गांवों में मोबाइल, बिजली और इंटरनेट सुविधाओं की पूरी दुनिया है। हमारे किसान, मछुआरों, डेयरी फार्मर्स, महिलाएं, स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं। अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन उपलब्धियों की विशेषताएं ये हैं कि कुछ समय पहले तक यह नामुमकिन लगती थी। आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद, सपना और संकल्प है। यही एम्प्लेशन आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।

12 सालों की उपलब्धि को अंकों से नहीं माप सकते

25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में आज जितने कुल घर हैं, उससे ज्यादा घर हमने भारत में जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए हैं। इन 12 सालों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है, जिसे अंकों से नहीं मापा जा सकता। वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।



500 साल किया, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए

● राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार बोले सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)। राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की खबरों और एसआईटी जांच के बीच शुक्रवार को पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बयान दिया। अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि आपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक इंतजार किया है। 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। कोई अपराधी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने 15 दिनों तक किसी तरह की

बयानबाजी नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आएँ। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में देखने सुनने को मिला। उसके बाद ट्रस्ट के कहने पर हमने एसआईटी जांच बैठाई है।

जब तक जांच हो रही है कोई भी ऐसी अनर्गल बात न हो जो राम भक्तों की भावना को आहत करती हो। यह भी कहा कि किसी के पास इससे संबंधित दस्तावेजी सबूत हों तो एसआईटी को दे दे, वह जांच करेगी। प्रभु श्रीराम ने मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा दी है, ऐसे में सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि जांच के बीच बयानबाजी जांच



प्रभावित करती है। जांच के बाद किसी को कोई बात कहनी होगी तो एसआईटी से कह सकते हैं।

अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आएँ

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या और श्रीराम जन्मभूमि को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आएँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि राम भक्तों और जयश्रीराम का नारा लगाने पर लाठी-गोली चलाने वाले आज उपदेश देने चले हैं। यह लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या को सम्मान मिले। यह लोग अयोध्या को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या और यहां के लोगों को अपमानित करते हैं।

बाबर को मानने वाले लोग राम भक्तों के बदनाम कर रहे

सीएम योगी ने कहा कि जो लोग रामभक्तों को अपमानित करते थे, अपराधियों के कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते थे। जिन लोगों ने अब तक राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया, अपने विधायकों को भी जाने से रोका, वह लोग बाबर को मानने वाले लोग हैं। उनके ही विधायक मनोज पांडेय ने जब सभी विधायकों को अयोध्या लाने की बात कही तो उन्हें अखिलेश यादव ने फटकार दिया था। मनोज पांडेय को धुतकार कर भगा दिया था। आज मनोज पांडेय हमारी सरकार में मंत्री हैं। कहा कि यह लोग (अखिलेश) कभी अयोध्या नहीं आए और अयोध्या को बदनाम करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, इसे देखते रहिए। उन लोगों की सोच कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने तक ही सीमित रही है। हम लोग अयोध्या के विकास में लगे हैं। आज एक ही विधानसभा में 126 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वह लोग दोगले चरित्र के लोग हैं। उन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अयोध्या की पहचान का संकट खड़ा किया था। आज कांग्रेस भी बोल रही है।

ऑपरेशन टाइगर के बाद उद्धव को एक और झटका

● दावा-सांसदों के बाद अब विधायक भी बदलेगे पाला

मुंबई (एजेंसी)। ठाकरे गुट की शिवसेना के छह सांसदों द्वारा बगावत कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जाने का फैसला करने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 'ऑपरेशन टाइगर' की सफलता के बाद अब ठाकरे गुट के कुछ विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं और मानसून सत्र शुरू होने से पहले राज्य में बड़ा राजनीतिक



भूचाल आ सकता है, ऐसा दावा शिंदे गुट के शिवसेना विधायक बच्चू कडू ने किया है। बच्चू कडू ने एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रणनीति की सलाहना करते हुए कहा कि सांसद आ चुके हैं, अब कुछ विधायकों के भी आने की संभावना है। शिंदे साहब की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। जो नेता और जनप्रतिनिधि भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, वे अपने फैसले ले रहे हैं। इस बीच, शिंदे गुट के नेताओं ने पहले भी दावा किया था कि ठाकरे गुट के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, ठाकरे गुट के 16 विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी शिंदे गुट की ओर से किया गया था।

सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा

पिछले कुछ दिनों से 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में जोर-शोर से हो रही है। खबरें हैं कि ठाकरे गुट के छह सांसदों ने अलग समूह बनाकर आगे चलकर शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी दिखाई है। इन घटनाक्रमों के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस पूरी प्रक्रिया को 'ऑपरेशन टाइगर' का नाम दिया गया है और इसे ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इन राजनीतिक घटनाओं के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई है।

संक्षिप्त समाचार

सड़क से सदन तक सामने आई टीएमसी की लड़ाई

● अलग-अलग बैठे बागी और ममता समर्थक विधायक

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को जब नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो टीएमसी के दोनों गुटों के बीच दरारें साफ दिखाई दीं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बागी गुट के विधायक विपक्ष में अलग-अलग बैठ पर बैठे। इस बीच, ममता बनर्जी के वफादार नेताओं ने मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा में अलग कमरा दिए जाने और बोलने के लिए अलग से वक्त देने की मांग की। राज्यपाल आरएन रवि ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम



बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई और बीजेपी की सरकार बनने के बाद वसूली करने वाले गिरोहों की नकेल कसी गई है। चुनाव नतीजें आने के बाद टीएमसी में बगावत हुई थी और लगभग 58 से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था। इस गुट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना और विधानसभा के स्पीकर ने इसकी मंजूरी भी दे दी। ममता बनर्जी के खेमे में शामिल पार्टी के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय और टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता कुणाल घोष मुख्यमंत्री से मिले। कुणाल घोष ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे लोग बागी गुट का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल के नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

यूएस-ईरान शांति वार्ता पर फिर संकट

● इजरायल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी, वेंस का स्विट्जरलैंड दौरा रद्द

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच अभी दो दिन पहले ही जिस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, वह शुरू होने से पहले ही पूरी तरह खतरे में पड़ना कारगर आ रहा है। एक तरफ जहां इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में रातभर भीषण बमबारी की है, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ, स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका-ईरान की बेहद महत्वपूर्ण शांति वार्ता को टाल दिया गया है। अमेरिकी



राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की मौजूदगी में बुधवार को ही वसाय के महल (फ्रांस) में अमेरिका और ईरान के बीच एक शुरुआती शांति समझौता हुआ था। इसका मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को रोकना था। इस समझौते में साफ कहा गया कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोक दी जाएगी। लेकिन इस समझौते के तुरंत बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहू ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है।

नर्मदापुरम् के 55 हजार 879 उपभोक्ताओं को मई माह में 57 लाख 19 हजार की छूट

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला सोलर ऑवर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ

भोपाल/नर्मदापुरम्। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मई 2026 के दौरान नर्मदापुरम् के कुल 55 हजार 879 उपभोक्ताओं को मई माह में 57 लाख 19 हजार रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में बिजली उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है।

कंपनी ने बताया है कि घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य, स्ट्रीट लाइट एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि को सोलर ऑवर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उपभोग की गई ऊर्जा पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 20 प्रतिशत तक की छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबन्ध मांग वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिवारों में स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें तथा स्मार्ट मीटर के उपयोग से होने वाले लाभों का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से सटीक रीडिंग, पारदर्शी बिलिंग एवं ऊर्जा खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो रही है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली की खपत को ट्रैक करने, ऊर्जा बचत करने तथा मोबाइल एप के माध्यम से कहीं से भी अपनी खपत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

स्मार्ट मीटर के फायदे

- ऊर्जा की खपत को ट्रैक कर नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है।
- बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।
- एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।
- ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।
- ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है।
- ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है।

बैतूल के 29 हजार 890 उपभोक्ताओं को मई माह में 28 लाख 54 हजार की छूट

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मई 2026 के दौरान बैतूल के कुल 29 हजार 890 उपभोक्ताओं को मई माह में 28 लाख 54 हजार रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है।

हरदा के 17 हजार 936 उपभोक्ताओं को मई माह में 16 लाख 72 हजार की छूट

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मई 2026 के दौरान हरदा के कुल 17 हजार 936 उपभोक्ताओं को मई माह में 16 लाख 72 हजार रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है।

रायसेन के 35 हजार 457 उपभोक्ताओं को मई माह में 29 लाख 85 हजार की छूट

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मई 2026 के दौरान रायसेन के कुल 35 हजार 457 उपभोक्ताओं को मई माह में 29 लाख 85 हजार रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है।

टीएमसी, शिवसेना के बाद अब पवार की बारी!

● सुनेत्रा-पार्थ के दिल्ली दौरे से हड़कंप, सामने दो विकल्प



मुंबई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों में बगावत के बाद राजनीति गरमाई हुई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मानसून सत्र तक लोकसभा में एनडीए सरकार का संख्याबल 360 हो सकता है।

इस सब के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र में सरगामी बढ़ा दी है। चर्चा हो रही है कि क्या बगावत का तूफान बरामती तक पहुंचेगा। अटकलें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) में बगावत हो सकती है।

सुनेत्रा पवार भी बढ़ा सकती हैं पावर- एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे के छह सांसद आने से कुल संख्या 13 हो जाएगी। ऐसे में शिंदे का कद दिल्ली में न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे बड़े मंत्री भी बन सकते हैं। सुनेत्रा पवार की अनुयायी वाली एनसीपी एनडीए का हिस्सा है लेकिन मोदी सरकार में कोई मंत्री नहीं है। ऐसे संभावना है कि अगर पांच सांसद पाला बदलकर सुनेत्रा की तरफ जाते हैं तो पार्टी के पास कुल सांसद छह हो जाएंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में एनसीपी को भी मंत्री पद मिल सकता है।

एलपीजी से लेकर साबुन-दवाइयां भी होंगी सस्ती

● यूएस-ईरान शांति समझौते से भारत को होंगे बड़े फायदे ● तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा ● एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, दाम स्थिर रहेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शुक्रवार को दोनों देश स्विट्जरलैंड के बर्न-स्टॉक रिजॉर्ट में ऐतिहासिक शांति वार्ता के लिए आमने-सामने होंगे। यहां समझौते के क्रियान्वयन और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को होने वाला प्रस्तावित शांति समझौता सिर्फ एक कूटनीतिक



सफलता नहीं, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित हो सकता है। दरअसल, भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए फायदा होगा।

फल-सब्जी और खाने-पीने के आइटम हो सकते हैं सस्ते

डीजल का उपयोग सिर्फ वाहनों तक ही सीमित नहीं है, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल खेती, कोल्ड स्टोरेज और माल ढुलाई में भी होता है। सब्जी-फल और दूसरे खाने पीने के सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट लागत अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा खाड़ी देशों के फर्टिलाइजर का भी कृषि में अहम योगदान है, ऐसे में अगर डीजल और खाद सस्ता होते हैं तो खाने-पीने की चीजों के दाम कम हो सकते हैं। कोल्ड फ्रीज, बॉडी लोशन, लिफ्टिक और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है। जूते-चप्पलों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है।

राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' हस्ताक्षर अभियान

● बोले-पेपर लीक, महंगी फीस और बेरोजगारी पर छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने को 'छात्रों की गूंज' नाम से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि यह अभियान पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का मंच बनेगा। राहुल ने छात्रों से अभियान से जुड़ने, अपने सुझाव देने और याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में अभियान का लिंक शेयर किया। लिखा कि जिन छात्रों के

सपने पेपर लीक, परीक्षा संबंधी समस्याओं या बढ़ती फीस की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए यह अभियान एक आवाज बनेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे तो उनकी मांगें उतनी ही मजबूती से सरकार तक पहुंचेंगी। राहुल गांधी ने वीडियो मैसेज में कहा- कोटा में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को देशभर के छात्रों का जबरदस्त समर्थन मिला। लाखों युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था पर उनकी प्रेजेंटेशन देखी और अपने विचार साझा किए।



शिक्षा का बढ़ता खर्च सबसे बड़ी चिंता

राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा का लगातार बढ़ता खर्च देश के लाखों परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। लाखों परिवार अपने बच्चों को नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने में भारी रकम खर्च कर रहे हैं। यह स्थिति चिंता का विषय है और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दे किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि पूरे देश के मुद्दे हैं। इसलिए छात्रों को खुलकर अपने अनुभव और सुझाव सामने रखने चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने दावा किया कि हर साल नीट परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्र और उनके परिवार से सिस्टम के जरिए 1.32 लाख करोड़ खर्च करवाए जाते हैं। यह रकम देश के पूरे शिक्षा बजट 1.40 लाख करोड़ के लगभग बराबर है। प्रियंका गांधी ने बुधवार रात एक्स पोस्ट में ये भी लिखा- मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोग माफ किए, वे 16 लाख करोड़ रुपए हैं। प्रियंका की यह टिप्पणी राहुल गांधी के कोटा दौरे के बाद आई। राहुल ने बुधवार को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत में शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते दबाव पर चर्चा की थी।

राष्ट्रपति मुर्मू को इन्दौर एयरपोर्ट पर दी गई भावभीनी विदाई



भोपाल (नप्र)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को इन्दौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर अन्तर्राष्ट्रीय विमानतल से अपने यात्रा का पहला पड़ाव पूर्ण कर आगे के निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हुईं। विमानतल पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सहित जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय विदाई दी। इस दौरान मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, क्षेत्रीय सांसद शंकर ललवानी, विधायक महेंद्र हाडिया,

विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़, महापौर इन्दौर पुष्पामित्र भागवत, कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विजय बी. नायर, कमिश्नर, संभागायुक्त इन्दौर डॉ. सुदाम खांडे, पुलिस कमिश्नर इन्दौर जॉन संतोष सिंह सहित जनप्रतिनिधि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कारोबारी से 17 लाख की ठगी

तीन गाड़ियां देकर नहीं दिए दस्तावेज, डुप्लीकेट चाबी से घर के बाहर से उठा ले गए वाहन

भोपाल (नप्र)। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी संचालक से परिचित व्यक्ति द्वारा कम कीमत में नई कारें बेचने का झांसा देकर 17 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित को भरोसे में लेकर तीन गाड़ियां दीं, लेकिन उनके दस्तावेज नहीं दिए। बाद में डुप्लीकेट चाबी से तीनों कारें घर के बाहर से उठा ले गया।

रेतघाट तलैया निवासी मुस्तकीम बैग (57) गैस एजेंसी संचालक हैं। उनकी पहचान छावनी निवासी मोहम्मद फैज से थी। पीड़ित के अनुसार फैज का उनके घर आना-जाना था और परिचित होने के कारण उन्होंने उस पर भरोसा किया।

बाद में पीड़ित को पता लगा कि आरोपी कार सेल्फ राइड के नाम पर विभिन्न शहरों से लाया था। जिसे उसने अपना बताकर बेचा और रकम हड़प ली। इसी तरह के एक मामले में हाल ही में अरेरा हिल्स पुलिस ने कार्रवाई की



और सेल्फ राइड के नाम पर कारों लेकर गिरबी रखने और बेचने वाले गिरोह का पर्दा फाश किया है।

दस्तावेज बाद में देने को बोला था- आरोप है कि फैज ने पैसे को जरूरत बताते हुए नई कारें कम दाम में बेचने की बात कही। जनवरी से मार्च के बीच उसने मुस्तकीम को थार जीप, एक्स्यूवी-300 और स्कॉर्पियो दीं। इसके बदले में 17 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने भरोसा दिलाया था कि तीनों वाहनों के दस्तावेज बाद में एक साथ देगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी

दस्तावेज नहीं दिए।

इसके बाद 26 अप्रैल की रात करीब 2 बजे फैज और उसके साथियों ने तीनों कारों को मुस्तकीम के घर के बाहर से उठा लिया। मुस्तकीम के मुताबिक तीनों कारों की चाबी उनके पास थी, इसके बावजूद आरोपियों ने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर वाहन ले गए। पूरा घटनाक्रम उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है।

चाबी मालिक के पास, फिर भी कैसे चली गईं कारें? - पीड़ित का

कहना है कि तीनों वाहनों की असली चाबी उनके पास थी। इसके बावजूद आरोपी डुप्लीकेट चाबी से कारें ले गए। इससे वाहन सुरक्षा और डुप्लीकेट चाबी तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।

दो महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप- मुस्तकीम ने मामले की शिकायत तलैया थाने में की थी। उनका आरोप है कि शिकायत के दो महीने बाद भी आरोपी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने दावा किया है कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना प्रभारी बोले मामले की जांच जारी- तलैया थाने के प्रभारी दीपक ढहरिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है। क्योंकि तुरी डील नकद में की गई और बिना लिखापट्टी के की गई थी, लिहाजा बारीकी से जांच की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

बरकतउल्ला विवि नाम

कायम रखने आज धरना

भोपाल। भारत की प्रथम निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री, स्वाधीनता सेनानी, वरिष्ठ शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार और भोपाल के महान सपूत बरकतउल्ला भोपाली के नाम पर स्थापित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का नाम कायम रखने की मांग को लेकर धरना 20 जून को शाम 5 बजे से, स्थानीय इतवार क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट हम्माल मजदूर सभा के कार्यालय के सामने दिया जाएगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि इस धरने में वामपंथी, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दलों और अमन, सद्भाव, सहिष्णुता के लिए प्रतिबद्ध जन संगठनों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव करके बरकतउल्ला भोपाली और भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के मूल्यों को अपमानित किया है। यह अनुचित और अक्षय्य है। इसका कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा।

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के

कुलगुरु का त्याग-पत्र स्वीकृत

प्रोफेसर विवेक शर्मा को मिला कुलगुरु का प्रभार

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु प्रो. एस. के. जैन द्वारा प्रस्तुत त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर दिया है। राज्यपाल पटेल ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत प्राप्त कुलाधिपति की शक्तियों के तहत विश्वविद्यालय के नये कुलगुरु की नियुक्ति होने तक कार्य संपादन के लिए संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रो. विवेक शर्मा को कुलगुरु के पद पर कार्य करने के लिए नामांकित किया है।

श्रद्धेय पं. माधवराव सप्रे के लिए

कलम ही जनसेवा और राष्ट्र

जागरण का साधन थी: मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलम को जनसेवा और राष्ट्र-जागरण का साधन बनाने वाले, प्रखर पत्रकार, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पं. माधवराव सप्रे जी की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि श्रद्धेय सप्रे जी ने साहित्य और पत्रकारिता जगत को समृद्ध किया। आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण को समर्पित उनकी कृतियां इस देश की अमूल्य निधि हैं।

भोपाल में 24 घंटे में ही बदली

पटवारी ट्रांसफर लिस्ट

46 में से 24 पटवारियों के तबादले रद्द वर्षों से जमे पटवारियों को फिर मिली राहत भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में पटवारियों के तबादलों की लिस्ट सिर्फ 24 घंटे में ही बदल गई। इससे प्रशासनिक निर्णय पर सवाल खड़े हो गए हैं। 15 जून को जारी स्थानांतरण आदेश में जिन पटवारियों को वर्षों से एक ही तहसील में पदस्थ रहने के कारण हटाया गया था, उनमें से आधे से अधिक को अगले ही दिन राहत मिल गई। महज 24 घंटे के भीतर जारी संशोधित सूची में 46 में से 24 पटवारियों के नाम हटा दिए गए, जिससे तबादले निरस्त हो गए।

कलेक्टर कार्यालय ने 15 जून को 46 पटवारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया था। इनमें अधिकांश ऐसे कर्मचारी शामिल थे जो 5 से 8 वर्षों से हजूर और कोलार तहसीलों में पदस्थ थे। कुछ पटवारी अपनी गृह तहसील में भी कार्यरत थे। लेकिन 16 जून को कैबिनेट बैठक के बाद स्थानांतरण की समयसीमा बढ़ने पर दर रात नई सूची जारी हुई, जिसमें कई नाम बाहर कर दिए गए।

सूत्रों के मुताबिक संशोधित सूची में शामिल 30 पटवारियों में से बड़ी संख्या हजूर और कोलार क्षेत्र की रही। आरोप है कि प्रभावशाली संपर्कों के जरिए कुछ पटवारियों ने अपने नाम सूची से हटवा लिए।

स्टिंग में सामने आए नामों को भी मिली राहत

संशोधित सूची से हटाए गए पटवारियों में निधि नेमा और किशोर सिंह दांगी भी शामिल हैं। दोनों नाम दो वर्ष पहले हुए एक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे, जिसमें कथित तौर पर पैसें के लेन-देन के वीडियो सामने आए थे।

मुख्यालय एवं विद्युत गृहों के विशेषज्ञ अभियंताओं की संयुक्त समन्वय टीम गठित

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने विद्युत गृहों के निर्बाध

संचालन के लिए बनाया तकनीकी निगरानी मॉडल

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने अपने ताप एवं जल विद्युत गृहों की वार्षिक रखरखाव एवं पूंजीगत ओवरहॉल गतिविधियों के उपरान्त इकाइयों के अधिक सुरक्षित, दक्ष एवं निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निगरानी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनजीत सिंह ने कहा कि कंपनी का विश्वास है कि मशीनों की तरह कार्य प्रणालियों का भी समय-समय पर मूल्यांकन एवं पुनर्विचार आवश्यक होता है। इससे न सिर्फ बेहतर सभाजन उभर कर आते हैं बल्कि कंपनी भी नवाचार के साथ निरंतर विकसित होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। उन्होंने कहा कि यह पहल तकनीकी विशेषज्ञता, सहभागिता एवं नवाचार को बढ़ावा देते हुए विद्युत उत्पादन की विश्वसनीयता को नई मजबूती प्रदान करेगी।



क्या होती है वार्षिक एवं पूंजीगत ओवरहॉल प्रक्रिया

विद्युत उत्पादन इकाइयों में वार्षिक एवं पूंजीगत ओवरहॉल एक निर्धारित एवं व्यापक रखरखाव प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उपकरणों की कार्यक्षमता बनाए रखना, संभावित खराबियों को रोकना तथा संयंत्रों की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। वार्षिक ओवरहॉल सामान्यतः प्रत्येक एक से दो वर्षों के अंतराल में किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण उपकरणों का निरीक्षण, आवश्यक मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पुर्जों का प्रतिस्थापन किया जाता है। वहीं पूंजीगत ओवरहॉल एक विस्तृत तकनीकी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः चार से छह वर्षों के अंतराल में किया जाता है, जिसमें प्रमुख मशीनों को खोलकर उनकी व्यापक मरम्मत, उन्नयन तथा तकनीकी सुधार किए जाते हैं, जिससे संयंत्रों की आयु एवं दक्षता में वृद्धि होती है।

निरंतर निगरानी और विश्लेषण करेगी टीम

गठित समन्वय टीम ओवरहॉल अवधि के दौरान संबंधित विद्युत गृहों का नियमित भ्रमण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि पिछली ओवरहॉल अवधि के बाद आई विभिन्न तकनीकी ट्रिपिंग के मूल कारणों का उचित विश्लेषण कर आवश्यक सुधारत्मक उपाय अपनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी कार्यों की गतिविधियों की गुणवत्ता को भी समीक्षा की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ओवरहॉल गतिविधियों का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाए एवं विद्युत गृह में गठित गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा उसका सत्यापन किया जाए।

4 ताप व 10 जल विद्युत गृह से होता है 5492 मेगावाट बिजली उत्पादन

वर्तमान में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के चार ताप विद्युत गृह अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी, संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसंगपुर व श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया द्वारा कुल 4570 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पावर जनरेटिंग कंपनी के 10 जल विद्युत गृहों गांधीसागर, पंच जल विद्युत गृह तोतलाडोह, रानी अंबेतीबाई सागर जल विद्युत गृह के टोंस, सिलपार, देवलौद, झिन्ना जल विद्युत गृह, बिरसिंगपुर जल विद्युत गृह, राजघाट जल विद्युत गृह एवं मड़ोखड़ा जल विद्युत गृह द्वारा कुल 915 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। रतगुडिया ग्राउंडमाउंटड सोलर प्रोजेक्ट से कुल सात मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होता है। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5492 मेगावाट है।

सिग्नल केबल चोरी: मुंबई-हावड़ा

रूट पर तीन घंटे ट्रेनें थमीं, 19 हुईं लेट

सतना में केवल लेकर भाग रही दो महिलाएं गिरफ्तार

सतना (नप्र)। मुंबई-हावड़ा रेलखंड पर सतना-मैहर के बीच लगरगावां स्टेशन के पास गुरुवार को सिग्नल की 7 मीटर केबल चोरी हो गई। इस घटना के कारण रेल संचालन लगभग तीन घंटे तक प्रभावित रहा, जिससे अप और डाउन लाइन की 19 ट्रेनें देरी से चलीं। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केबल लेकर भाग रही दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। सिग्नल विभाग के कर्मचारियों ने केबल काट कर ले जा रही महिलाओं को देखा और तत्काल आरपीएफ को सूचित किया। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम ने पीछा कर दोनों आरोपियों को चोरी की गई केबल के साथ पकड़ लिया। बाद में इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त केबल को जोड़कर रेल संचालन को सामान्य किया।

इस घटना से प्रभावित होने वाली ट्रेनों में अप लाइन की अयोध्या-एलटीटी, गोरखपुर-एलटीटी, दानापुर-एसएमवीटी, दरभंगा-अहमदाबाद, वाराणसी-एकता नगर और सतना-कटनी मेमू शामिल थीं।

आदिवासियों की जमीन बिक्री मामले की जांच की मांग

जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की, बोले-8 साल में 3 लाख एकड़ जमीन बिकी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों की बिक्री और इसकी अनुमति दिए जाने के मामलों की जांच की मांग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले सात से आठ वर्षों में करीब तीन लाख एकड़ आदिवासी जमीन बेची गई है और इसमें भाजपा नेताओं, मंत्रियों, विधायकों तथा उद्योगपतियों की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चप्पू की उपयोगिता बहुत अधिक होती है क्योंकि वही नाव को पार लगाता है।

भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब एक करोड़ 53 लाख आदिवासी परिवार रहते हैं। नियमों



के अनुसार आदिवासी की जमीन सामान्य वर्ग के लोग सीधे नहीं खरीद सकते और इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आया है कि करीब 1

नीट के लिए हाई अलर्ट, सेंटरों पर सीसीटीवी-जैमर लग रहे स्टूडेंट्स के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन, टाइम डिस्टर्ब की व्यवस्था रहेगी, तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर भी मिलेगा

भोपाल (नप्र)। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट जी) 21 जून को है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रदेश के सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए हर सेंटर के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई जाएगी। किसी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर वही तैनात मिलेंगे।

भोपाल में कुल 13 हजार 774 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन, पुलिस के साथ रेलवे भी तैयारी कर रहा है। 32 केंद्र प्रभारियों के साथ कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को वन-



टू-वन मॉडिंग की। इसमें बताया गया कि कई बार दो से तीन सेंटरों के नाम एक जैसे होते हैं, जिससे परीक्षार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उन्हें केंद्र का नाम और स्थान क्लियर रखें।

हमीदिया रोड पर जो सेंटर है, उसके रास्ते में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को देरी हो सकती है। इसलिए पुलिस गाड़ियों को तुरंत हटा दें। पुराने शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। बैरिकेडिंग में सेंटर का नाम छिप सकता है। इसलिए सेंटर की ओर रास्ता दिखाने वाले बोर्ड लगेंगे।

सरकार बनने पर कांग्रेस करेगी समीक्षा

पटवारी ने आरोप लगाया कि यह जमीन भाजपा नेताओं से जुड़े लोगों और कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों में भाजपा नेताओं के डायरेक्टर या अन्य रूपों में जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पटवारी ने आरोप लगाया कि इन जमीनों की अनुमति पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में दी गई। उन्होंने राष्ट्रपति से मामले का संज्ञान लेने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को पूरी जानकारी देकर जांच करानी चाहिए और मामले की समीक्षा कर तथ्य जनता के सामने रखे जाने चाहिए। पटवारी ने कहा कि वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों की जमीनों की बिक्री की समीक्षा की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से गई है, उसे वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

दिविजय सिंह के वायरल वीडियो पर बोले पटवारी

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि उनका और पूर्व मुख्यमंत्री दिविजय सिंह का रिश्ता पिता-पुत्र जैसा है। उन्होंने कहा कि दिविजय सिंह ने हमेशा उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन किया है तथा राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा है। पटवारी ने वायरल वीडियो को भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि यह वीडियो मैनपुलेट किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। सीएम पर पलटवार, चप्पू की उपयोगिता बहुत अधिक होती है क्योंकि वही नाव को पार लगाता है पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जवाब देने के बजाय विपक्ष के नेताओं के लिए नैसिखिया, दो कांडी का और पप्पू का चप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि चप्पू की उपयोगिता बहुत अधिक होती है क्योंकि वही नाव को पार लगाता है, जबकि अहंकार और अभद्रता केवल लोकातार्थिक मूल्यों को डुबाने का काम करते हैं।

संपादकीय अब झारखंड में खेला!

मग्न के बाद अब झारखंड में राज्यसभा चुनाव में 'खेला' हो गया। वहां क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस प्रत्याशी को हार हो गई और भाजपा समर्थक निर्दलीय परिमल नाथवानी की जीत हो गई। इस हार के बाद विपक्षी 'इंडिया गठबंधन' इस हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का खेल शुरू हो गया। गौरतलब है कि गुरुवार को 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। इनमें से 19 सीटें एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को 6 और एक सीट मिजोरम की जोराम पीपुल्स मुवमेंट (जीपीएम) को मिली। 23 सीटों पर उम्मीदवार निर्बिरोध चुने गए। जबकि 3 सीटों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में NDA और इंडिया ब्लॉक को एक-एक सीट का फायदा हुआ। लेकिन बड़ा खेला झारखंड में हुआ। वहां रास की दो सीटों पर चुनाव होना था। पार्टीवार विधायकों की संख्या के हिसाब से एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को तथा एक कांग्रेस को मिलनी थी। लेकिन इस चुनाव में एक तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी खड़े हो गए। चूंकि भाजपा के पास सीट जिताने का संख्याबल नहीं था, इसलिए उसने नाथवानी को समर्थन दे दिया। नाथवानी को 28 वोट मिले। जबकि झामुमो के बैद्यनाथ राम चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने यहां से प्रणव झा को टिकट दिया था। इसको लेकर झामुमो ने पहले आपत्ति भी जताई थी। लेकिन कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी कायम रखी। नतीजा क्रॉस वोटिंग के रूप में सामने आया। यहां 3 अवेध वोट पड़े। कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 20 वोट ही मिले। इस हार के बाद कांग्रेस नेता और झामुमो प्रभारी के. राम ने आरोप लगाया कि उसके प्रत्याशी को जिताने में आरजेडी और लेफ्ट ने साथ नहीं दिया। लेकिन सीटों-आई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि माले के दोनों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग की बात पूरी तरह से गलत है। हमने गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन किया है। जबकि आरजेडी के केन्द्रीय महासचिव महासचिव भोला यादव ने कहा कि मैं वहां एजेंट था। मेरे सामने चार विधायकों ने दिखाकर वोट दिया है। बिना किसी जांच के राजू जैसे नेता कहते हैं कि आरजेडी ने धोखा दिया है। हमें नहीं लगता कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिला सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड में कुल 81 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की थी। मौजूदा स्थिति में एनडीए के 24, झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के 56 और जेकेएलएम का एक विधायक है। इस चुनाव के बाद राज्यसभा में एनडीए के पास 151 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत से 29 ज्यादा है। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास में सिर्फ 65 सीटें हैं। अन्य के पास में 26 सीटें हैं। टोपमशी में फूट के बाद 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। जिससे सदन में 3 सीटें खाली हो गई हैं। खेला तो कर्नाटक विधान परिषद के चुनाव में भी हुआ। वहां मुख्यमंत्री शिवकुमार सत्ताधारी कांग्रेस ने विधान परिषद की 7 सीटों में से 5 सीट पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी पार्टी बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें ही गईं। क्रॉस-वोटिंग को लेकर सीएम शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने किसी से कोई समर्थन नहीं मांगा था। इस चुनाव नतीजे के बाद कर्नाटक विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 39 हो जाएगी। जबकि बीजेपी को जेडीएस की संख्या घटकर क्रमशः 28 और 6 रह जाएगी। हालांकि झारखंड के खेला की चर्चा हुई। इसका एक बड़ा कारण राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी है। आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में मदद नहीं की।

समान नागरिक संहिता



डॉ. लोकेन्द्रसिंह कोट
लेखक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में अध्यापक हैं।

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा और धार्मिक परम्पराओं की ऐसी बहुरंगी छटा दिखाई देती है जो विषय में अद्वितीय है। इसी विविधता के बीच एक प्रश्न स्वतंत्रता के समर्थन से ही भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा है—क्या सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है समान नागरिक संहिता (यूसीसी)। यह केवल एक कानूनी विषय नहीं है, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ विमर्श है। इसलिए यूसीसी पर चर्चा होते ही समाज में समर्थन और विरोध दोनों स्वर मुखर हो जाते हैं। जब संविधान सभा में भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तब यह प्रश्न भी उठा कि क्या विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। उनका मानना था कि नागरिक मामलों में समानता लोकतंत्र की आधारशिला है। हालाँकि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इसे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया बल्कि संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार यूसीसी संविधान की मूल भावना का हिस्सा तो बना, लेकिन तत्काल लागू नहीं किया गया। भारत में अभी अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) लागू हैं। हिन्दू कानून, हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों पर मुस्लिम: हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम आदि लागू होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक, मेहर, उत्तराधिकार आदि विषयों पर शरीयत आधारित प्रावधान लागू होते रहे हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धी परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MP/PHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विवाद लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध नहीं है।

अमेरिका-ईरान : केवल युद्धविराम पर्याप्त नहीं

नजरिया

राज कुमार सिन्हा
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मध्य-पूर्व की भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगी। होम्सुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस की निबंध आपूर्ति बहाल होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल गिरावट आएगी, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। समुद्री मार्ग के खुलने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्पलाई चैन की बाधाएं दूर होंगी, जिससे एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। भारत, चीन और जापान जैसे बड़े तेल आयातक देशों को राजकोषीय घाटा कम करने और अपनी मुद्रा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का 80 फिसदी से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। युद्ध विराम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट ब्रूड की कीमतें नीचे आएंगी, जिससे भारत का आयात बिलत कम होगा और राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहेगा। भारत का अधिकांश तेल और एलपीजी होम्सुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। युद्ध विराम से इस समुद्री मार्ग पर हमलों का खतरा खत्म हो जाएगा, जिससे भारत को बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति होती रहेगी। फारस की खाड़ी में तनाव कम होने से जहाजों का बीमा प्रीमियम घटेगा। इससे भारतीय तेल कंपनियों की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी। यदि इस युद्ध विराम के बाद भविष्य में ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं, तो भारत दोबारा ईरान से सस्ते और रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात शुरू कर सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा होगा। 26 अप्रैल 2026 को भारत के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद से चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट गहरे संकट में था। इस नए युद्ध विराम समझौते से भारत के लिए नई उम्मीदें जगी हैं।

प्रतिबंधों की अवधि खत्म होने के बाद भारत ने वहां से अपने कुछ कर्मचारी हटा लिए थे और अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाई थी। युद्ध विराम के बाद भारत इस रणनीतिक बंदरगाह पर कारगो संचालन को फिर से पूरी तरह शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत को सीधा रास्ता देता है। शांति समझौते के कारण समुद्री मार्गों पर तनाव खत्म होने से भारत का यह महत्वाकांक्षी व्यापारिक कॉरिडोर एक बार फिर सुरक्षित और सक्रिय हो जाएगा। भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जमीनी रास्ते की जरूरत नहीं रहेगी। मुंबई या कंडला बंदरगाह से सामान सीधे ओमान की खाड़ी के रास्ते ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचेगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी बचत होगी। चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए भारतीय सामान ईरान के रेलवे नेटवर्क का उपयोग करके कैस्पियन सागर और वहां से सीधे रूस व यूरोप तक पहुंच सकेगा। यह मार्ग पारंपरिक स्वजे नहर मार्ग की तुलना में 30 फिसदी सस्ता और 40 प्रतिशत तेजी से पहुंचेगा। संघर्ष विराम से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होगी, जिससे व्यापक युद्ध की आशंका टलेगी। लेबनान, यमन और इराक जैसे देशों में परोक्ष युद्धों के थपने की संभावनाएं बनेगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस युद्ध विराम का स्वागत किया है क्योंकि उनका ध्यान अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर है, जिसके लिए क्षेत्रीय शांति अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका- ईरान में जंग खत्म करने पर बनी सहमति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जंग से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक परेशानी पैदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस युद्ध विराम का पुरजोर स्वागत किया है और इसे मध्य-पूर्व में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध को टालने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मांग की है कि इस शांति काल का उपयोग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी क्षेत्रीय देशों से संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री

कानूनों का सम्मान करने की अपील की है ताकि वैश्विक व्यापारिक जहाज सुरक्षित आ -जा सकें। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि वे इस अस्थायी युद्ध विराम का उपयोग एक दीर्घकालिक और स्थायी राजनयिक समाधान खोजने के लिए करें। आगामी 19 जून को 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम को एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संधि में बदलने के लिए स्विट्जरलैंड में एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य ईरान के यूरिनियम संवर्धन को परमाणु हथियार बनाने के स्तर से बहुत नीचे लाना है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को ईरान के सभी परमाणु केंद्रों तक बिना किसी बाधा के सीधे पहुंच देने पर बात होगी। वार्ता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित होगा कि ईरान लेबनान में हिज्बुल्लाह, यमन में हूती विद्रोहियों और इराक एवं सीरिया के सशस्त्र समूहों को वित्तीय और सैन्य सहायता देना पूरी तरह बंद करे। इसके बदले में ही इजराइल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल विकास और ड्रोन तकनीक के निर्यात पर कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा, जिसका इस्तेमाल हालिया संघर्षों में हुआ था। यदि ईरान ऊपर दी गई शर्तों को चरणबद्ध तरीके से मानता है, तो अमेरिका ईरान के तेल और बैंकिंग क्षेत्रों पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हमेशा के लिए हटाने का एक टाइमलाइन जारी करेगा।वार्ता की शुरुआत में ही अमेरिका ईरान करीब 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति को ड्रीज़िंग करेगा। साथ ही, खाड़ी देशों के सहयोग से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित 300 अरब डॉलर के फंड को औपचारिक रूप दिया जाएगा। जबकि 28 फरवरी से अब तक ईरान के युद्ध में अमेरिका करीब 10 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में ईरान एक बेहद प्रभावी और कूटनीतिक रूप से मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। जबकि पारंपरिक युद्ध में अमेरिका के पास अपार सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता है, फिर भी ईरान ने कई रणनीतिक मोर्चों पर सफलता हासिल की है।भारी हथियारों या विमान वाहकों पर निर्भर रहने के बजाय, ईरान ने उन्नत मिसाइलों और ड्रोंनों का उपयोग करके अमेरिका और उसके सहयोगियों के

बुनियादी ढांचे पर भारी लागत का दबाव डाला है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने में शामिल रहे हैं। परन्तु अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते को लेकर इजरायल का रवैया पूरी तरह से असहमत और आक्रामक है।इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और वित्त मंत्री बेतलेल स्मोत्रिच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह शांति समझौता इजरायल को किसी भी तरह से नहीं बांधता है। उनके अनुसार, इजरायल एक संप्रभु राष्ट्र है और वह अमेरिका के इस समझौते के आगे नहीं झुकेगा। इजरायली नेताओं का मानना है कि इस डील से ईरान को अरबों डॉलर का फायदा होगा और उसका परमाणु ढांचा जस का तस रह जाएगा। इसलिए, इजरायल ने चेतावनी दी है कि यदि उसे अपनी सुरक्षा खतरे में लगे, तो वह ईरान पर 'परी ताकत' के साथ हमला करने के लिए स्वतंत्र है। सकारात्मक घटनाक्रम के बावजूद, बेरूत में ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह के साथ इजराइल की चल रही सैन्य शत्रुता के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे समझौते के खतरे में पड़ने की आशंका है। विगत रविवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल से आग्रह किया कि वह समझौते को न बिगाड़े, जब इजराइल की सेना ने हिज्बुल्लाह पर हमले किए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा, 'इजराइल अपनी धरती पर गोलीबारी बंदारंश नहीं करेगा।' अतः अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम केवल दो देशों के बीच तनाव कम होने की घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को पुनर्निर्भाषित करने वाला महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता कई चुनौतियों पर निर्भर करेगी। विशेष रूप से इजरायल का आक्रामक रुख इस शांति प्रक्रिया को कभी भी अस्थिर कर सकता है।इसलिए केवल युद्धविराम पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सभी पक्षों को पारस्परिक विश्वास, कूटनीतिक धैर्य और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आधार पर दीर्घकालिक समाधान विकसित करना होगा। यदि ऐसा संभव हो सका, तो यह समझौता केवल एक युद्ध को रोकने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 21वीं सदी में सहयोग, संवाद और साझा सुरक्षा पर आधारित नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखने वाला ऐतिहासिक पड़ाव बन सकता है।

एक राष्ट्र की अनेक परंपराओं में समानता की तलाश

तीन तलाक विवाद

हाल के वर्षों में तत्काल तीन तलाक का मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। शायरा बानो बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। इस निर्णय को कई लोगों ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना।

हाल के वर्षों में तत्काल तीन तलाक का मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। शायरा बानो बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। इस निर्णय को कई लोगों ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना।

नागरिकों के लिए एक समान उत्तराधिकार और विवाह कानून होने तो महिलाओं के अधिकार अधिक सुरक्षित होंगे।

2. संविधान की समानता की भावना: भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। समर्थकों का कहना है कि जब आपराधिक कानून सबके लिए समान हैं तो नागरिक कानून भी समान होने चाहिए।

3. राष्ट्रीय एकीकरण: एक देश में अलग-अलग नागरिक कानून कई बार विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। समान कानून नागरिकता की साझा पहचान को मजबूत कर सकते हैं।

4. कानूनी सरलता: अदालतों में अनेक विवाद इस कारण जटिल हो जाते हैं क्योंकि अलग-अलग समुदायों पर अलग-अलग कानून लागू होते हैं। यूसीसी से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल हो सकती है।

यूसीसी के विरोध में प्रमुख तर्क

1. धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न: विरोध करने वालों का कहना है कि भारत केवल एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक सभ्यता भी है। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान का हिस्सा हैं।

2. विविधता पर प्रभाव: भारत की शक्ति उसकी विविधता है। आलोचकों का तर्क है कि एक ही कानून विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं की विशिष्टताओं को कमजोर कर सकता है।

3. अल्पसंख्यकों की आशंकाएँ: कई अल्पसंख्यक समुदायों को भय है कि कहीं यूसीसी बहुसंख्यक परम्पराओं को ही राष्ट्रीय कानून का रूप न दे दे। इसलिए वे व्यापक संवाद और सहमति की मांग करते हैं।

4. आदिवासी समुदायों का प्रश्न: भारत के अनेक आदिवासी समाजों की अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएँ हैं। उनकी भूमि, विवाह और सामाजिक संरचनाएँ विशिष्ट हैं। इसलिए यूसीसी बनते समय इन समुदायों की परम्पराओं की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

विषय के अनेक देशों में नागरिक कानून समान हैं। फ्रांस में

धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानून लागू है और व्यक्तिगत मामलों में धर्म आधारित अलग कानून नहीं है। 1920 के दशक में तुर्की ने नागरिक कानूनों में व्यापक सुधार किए। इंडोनेशिया जैसे देशों में कुछ मामलों में धार्मिक कानूनों और नागरिक कानूनों का मिश्रित मॉडल देखे को मिलता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्येक देश अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था विकसित करता है।

क्या यूसीसी का अर्थ धार्मिक हस्तक्षेप है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। यूसीसी पूजा-पूजति, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार या आस्था से संबंधित विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता। यह केवल नागरिक मामलों से संबंधित है। कोई व्यक्ति किस प्रकार पूजा करेगा, कौन-सा त्योहार मनाएगा या कौन-सी धार्मिक परम्परा अपनाएगा—यह यूसीसी का विषय नहीं है।

भारत जैसा बहुलतावादी समाज केवल कानून बनाकर नहीं चल सकता। यहाँ संवाद, सहमति और संवेदनशीलता आवश्यक है। यदि यूसीसी को सफल बनाना है तो कुछ कदम आवश्यक होंगे जैसे व्यापक जनसंवाद जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से परामर्श हो, आदिवासी समुदायों की विशिष्टताओं का संरक्षण हो, चरणबद्ध क्रियान्वयन हो, राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, समानता और विविधता के बीच संतुलन बनाया जाए। समान नागरिक संहिता केवल कानून का प्रश्न नहीं है; यह उस भारत की परिकल्पना से जुड़ा है जहाँ समानता और विविधता दोनों साथ-साथ चल सकें। एक ओर संविधान का आदर्श है कि सभी नागरिक समान हों, दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक वास्तविकता है जिसमें अनेक परम्पराएँ और पहचानें रह-रहित हैं। इसलिए यूसीसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह समानता को बढ़ाते हुए विविधता का सम्मान कितनी संवेदनशीलता से कर पाता है।

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा हमें यही सिखाती है कि स्थायी समाधान टकराव से नहीं, संवाद से निकलते हैं। समान नागरिक संहिता भी तभी सफल होगी जब वह किसी समुदाय की हार या जीत नहीं, बल्कि न्याय, समान अवसर और संवैधानिक मूल्यों की सामूहिक विजय के रूप में स्थापित हो सके। अंततः प्रश्न केवल यह नहीं है कि यूसीसी लागू होगा या नहीं, बल्कि यह है कि भारत समानता और विविधता के बीच किस प्रकार का संतुलन स्थापित करता है। यही संतुलन भविष्य के भारत की दिशा में चल करेगा।

जवाबदेही किस चिड़िया का नाम है?

मासूम उदास चेहरा अपन के जेहन में घूम जाता है। मैं यारों के बीच इन पर बहस उकेरना चाहता था मगर उस रोज़ टिए पर दादू के अलावा कोई आया ही नहीं। बोले- 'तुम्हारी सोच नकारात्मक हो गई है, सांतिभिया। दुश्चारियों आईपीएल से पहले कम थी क्या?'

'नहीं दादू, दुश्चारियों तो आईपीएल के दरम्यान भी रहीं मगर निजाम ने हर शाम मस्ती में बिताने का फुल बंदोबस्त कर रखा था। उसने सस्ता डाटा भी मुहैया करा रखा था। नहीं करा पाया निजाम तो बस! आटा सस्ता नहीं करा पाया।'

दादू बोला - 'हर समय महंगे आटे का रोना लेकर बैठ जाते हो तुम, सांतिभिया। आईपीएल खत्म हुआ तो क्या! रील एन्जॉय कीजिए। हर समय रोते मत रहिए। सीबीएसई की परीक्षा के आगे जहाँ और भी हैं। क्या हो जाएगा एक पीढ़ी पूरी अनपढ़ हो रही ली तो!! जो पढ़े लिखे हैं वे कौनसे नैतिक काम कर रहे हैं? पढ़ा-लिखा बिका हुआ जज, बिका हुआ अफसर, बिका हुआ चुनाव अधिकारी, बिके हुए हाकिम, मुलाजिम, उतने ही बिके बिके से सम्पादक और पत्रकार पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? बिके हुए पढ़े लिखे समाज से बेहतर है एक पूरी

पीढ़ी का अनपढ़ अनबिका रह जाना। करियर और रोज़गार के गम मत पालिए सांतिभिया क्रिकेट का अफगानिस्तान दौरा एन्जॉय कीजिए। महंगे पेट्रोल के गम को वैभव सूर्यवंशी के छक्कों, जोफ़्रा आचर की यर्कॉरों में भूल जाइए।'

मैंने कहा - 'ऐसे कैसे हो सकता है दादू? नाती ट्वेल्थ में नाईटी एट परसेंट पर कॉफिडेंट था। उसके रोल नंबर पर किसी और की कॉपी स्कैन हो गई है। दूसरावाला दो साल से नीट की तैयारी कर रहा था। कोचिंग क्लास की फीस ने पहले ही बजट घाटे में ला दिया है। आईपीएल में रन रेट के ऊपर-नीचे होने से जिंदगी हलाकान नहीं होती, घर के बजट का रन रेट गिरने से होती है। अपन के बजट का विकेट तो महीने के पहले ओवर में ही गिर जा रहा है। न पॉवर बचा है न प्ले। दो महीने तक टीवी का रिमोट जिस तरह का 'स्ट्राइक रेट' दिखाता था, अब वह थम गया है। उसकी जगह डॉलर के रेट ने ले ली है। सिक्स के काउंटर पर इन्क्रिजिंग नंबर देखने की लत लग गई थी, अब पेट्रोल डिस्पेंसर के घटते काउंटर ने टेंशन बढ़ा दी है। एक बात बताओ दादू मुझे के ये 'बक' कभी तो कहीं तो 'स्टॉप' करते होंगे?'

'ये नया निजाम है सांतिभिया, वजीर-ए-तालीम से लेकर वजीर-ए-आजम तक, स्टॉप करने तो दूर बक अब किसी को टेबुल के आस पास फटकने भी नहीं पाते। झेड-प्लस सिक्वुरिटी लगी होती है कि परिदा भी पर नहीं मार पाता, जवाबदेही किस चिड़िया का नाम है? वैसे निजाम के कसिडरेशन में है कि आईपीएल के टाईम स्लॉट में क्या नया लाए जाए कि जेन-जी जंतर जंतर पहुंचने की बनिस्वत स्टैंडियम की दीर्घाओं में नजर आए। वो चियर-लीडर्स के टुककों में गिरते सैंसेक्स को भूल जाए। अवाग को जीवन की आपाधापी से निजात दिलापाना शायद उसके वश में नहीं रहा तो क्यों न उसे रील के समंदर में स्कूबा ड्राइविंग का मजा लेने के लिए छोड़ दिया जाए। कोशिश में है निजाम कि साल में दो-चार आईपीएल आयोजित करवाए। जब तक स्क्रीन पर गेंद घूमती रहेगी, तब तक आप जैसे सिरफिरो का भेजा घूमेगा नहीं। वरना ये पपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, सैंकेम के बाउंसर आप को ज्यादा दिन सकारात्मक रहने नहीं देगे। जस्ट चिल माई डियर सांति, उबलने की जिम्मेदारी चाय पर छोड़ दीजिए। कड़क मीठी का कट एन्जॉय कीजिए और निकलिए।'

उस रोज़ टिए पर बहस लम्बी नहीं चली।



विश्व उत्पादकता दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं।



आधुनिक युग में सफलता का सबसे बड़ा पैमाना केवल यह नहीं रह गया है कि कोई व्यक्ति कितना काम करता है बल्कि यह है कि वह उपलब्ध समय और संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग करता है। आज जब प्रतिस्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रही है, तब उत्पादकता व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बन चुकी है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए 20 जून को 'विश्व उत्पादकता दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस लोगों, संस्थानों और उद्योगों को अपनी कार्यशैली का मूल्यांकन करने, समय प्रबंधन को बेहतर बनाने तथा अधिक प्रभावी एवं संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह दिवस केवल कार्यस्थलों पर अधिक उत्पादन करने का संदेश नहीं देता बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता, संतुलन और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग-अलग बातें हैं। कई लोग दिनभर काम में लगे रहते हैं लेकिन दिन के अंत में उनके पास उपलब्धियों की सूची बहुत छोटी होती है। इसके विपरीत, कुछ लोग सीमित समय में योजनाबद्ध तरीके से काम करके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। यही वास्तविक उत्पादकता है।

उत्पादकता का सामान्य अर्थ है कम संसाधनों, कम समय और कम प्रयासों में अधिक तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करना। अर्थशास्त्र में इसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की दक्षता से जोड़ा जाता है जबकि व्यक्तिगत जीवन में यह लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की क्षमता का परिचायक है। वास्तव में उत्पादकता केवल कार्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता, प्रभाव और परिणामों से भी जुड़ी होती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि उत्पादकता की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ निरंतर विकसित होती रही है। चौदहवीं शताब्दी में यांत्रिक घड़ियों के आविष्कार ने समय को व्यवस्थित रूप से मापना संभव बनाया। इससे लोगों ने समय के महत्व को समझा और कार्यों का बेहतर नियोजन शुरू किया। औद्योगिक क्रांति के दौर में उत्पादकता को नई दिशा मिली। वर्ष 1913 में उद्योगपति हेनरी फोर्ड द्वारा असेंबली लाइन प्रणाली की शुरुआत ने उत्पादन जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस प्रणाली ने कम समय में अधिक उत्पादन को संभव

बदलते दौर में उत्पादकता का बढ़ता महत्व

उत्पादकता का सामान्य अर्थ है कम संसाधनों, कम समय और कम प्रयासों में अधिक तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करना। अर्थशास्त्र में इसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की दक्षता से जोड़ा जाता है जबकि व्यक्तिगत जीवन में यह लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की क्षमता का परिचायक है। वास्तव में उत्पादकता केवल कार्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता, प्रभाव और परिणामों से भी जुड़ी होती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि उत्पादकता की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ निरंतर विकसित होती रही है। चौदहवीं शताब्दी में यांत्रिक घड़ियों के आविष्कार ने समय को व्यवस्थित रूप से मापना संभव बनाया। इससे लोगों ने समय के महत्व को समझा और कार्यों का बेहतर नियोजन शुरू किया।

बनाया और आधुनिक औद्योगिक दक्षता की नींव रखी। बीसवीं शताब्दी में उत्पादकता केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रही। प्रसिद्ध लेखक अनेस्ट हेमिंग्वे सुबह के शुरुआती घंटों में लेखन करके अपनी रचनात्मक उत्पादकता के लिए जाने गए। वहीं मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने 1943 में मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने यह समझाने में मदद की कि व्यक्ति की प्रेरणा और उसकी उत्पादकता के बीच गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं और उसे सम्मान व आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, तब उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। आज डिजिटल युग में उत्पादकता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तकनीक ने कार्य करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सहयोग उपकरण और ऑटोमेशन ने अनेक कार्यों को सरल, तेज और अधिक सटीक बना दिया है। हालांकि इसके साथ ही सोशल मीडिया, अनावश्यक सूचनाओं और डिजिटल विचलनों ने लोगों की एकाग्रता को भी प्रभावित किया है। इसलिए आधुनिक समय में उत्पादकता केवल अधिक मेहनत करने का नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने का विषय बन गई है।

समय एकमात्र ऐसा संसाधन है, जिसे न तो संग्रहीत किया जा सकता है और न ही वापस पाया जा सकता है। इसलिए सफल लोग समय को धन से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं। समय प्रबंधन की प्रभावी तकनीकें उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें

कार्यों की प्राथमिकता तय करना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, समय सीमा बनाना तथा महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान केंद्रित करना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करनी चाहिए। इसे अक्सर 'फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट' सिद्धांत कहा जाता है। जब व्यक्ति दिन की शुरुआत में ही सबसे चुनौतीपूर्ण

कार्यों को पूरा कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और शेष कार्य अपेक्षाकृत आसान लगने लगते हैं। इसी प्रकार कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना भी उत्पादकता बढ़ाने का प्रभावी तरीका है। आजकल विश्वभर में लोकप्रिय पोमोडोरो तकनीक भी समय प्रबंधन का एक सफल उपाय मानी जाती है। इसमें व्यक्ति लगभग 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करता है और फिर 5 मिनट का छोटा विराम लेता है। चार चक्र पूरे होने के बाद लंबा विश्राम किया जाता है। यह तकनीक

बहुकार्य (मल्टी टास्किंग) को अक्सर दक्षता का प्रतीक माना जाता है लेकिन अधिकांश शोध इसके विपरीत संकेत देते हैं। मानव मस्तिष्क वास्तव में एक समय में एक ही कार्य पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। बार-बार कार्य बदलने से मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए विशेषज्ञ 'सिंगल-टास्किंग' अर्थात् एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। उत्पादकता का संबंध केवल कार्यस्थल से नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी है।

मानसिक थकान को कम करती है और ध्यान केंद्रित रखने में सहायता करती है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ब्रेक लेना भी उतना ही आवश्यक है, जितना काम करना। लगातार कई घंटों तक काम करने से मानसिक क्षमता घटने लगती है और जुटियों की संभावना बढ़ जाती है। छोटे-छोटे विश्राम मस्तिष्क को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं तथा रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि विश्व की कई अग्रणी कंपनियां कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर विश्राम लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान भटकाने वाले कारकों पर नियंत्रण। आज सोशल मीडिया, अनावश्यक ई-मेल, मोबाइल नोटिफिकेशन और निरर्थक ऑनलाइन गतिविधियां उत्पादकता के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। शोध बताते हैं कि किसी बाधा के बाद पुनः पूरी एकाग्रता प्राप्त करने में कई मिनट लग सकते हैं। इसलिए काम के दौरान गैर-जरूरी सूचनाओं को बंद रखना और एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अधिक लाभदायक होता है।

संगठनों के स्तर पर भी उत्पादकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, स्पष्ट नीतियां, पारदर्शी संवाद और प्रभावी नेतृत्व किसी भी संस्था की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। आज अनेक कंपनियां डिजिटल सहयोग प्लेटफॉर्म, परियोजना प्रबंधन उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों का उपयोग करके कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही हैं। इससे समय की बचत होती है, समन्वय बेहतर होता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। उत्पादकता का अर्थ अधिक व्यस्त होना नहीं बल्कि अधिक सार्थक होना है। जब व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और प्रतिभा का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, तब वह न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व उत्पादकता दिवस हमें यही संदेश देता है कि जीवन की दौड़ में केवल तेज दौड़ना पर्याप्त नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना भी उतना ही आवश्यक है। यही उत्पादकता का वास्तविक मंत्र है और यही सफलता का सबसे मजबूत आधार भी।

रफ्तार का जाल

गंगा पाण्डेय



कुछ सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों घायल हो गए। ऐसी घटनाएं अब अपवाद नहीं रह गई हैं, बल्कि लगभग हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से से सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। विडंबना यह है कि एक ओर भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, आधुनिक राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया के सबसे चिंताजनक देशों में गिना जाने लगा है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.68 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 2023 में यह संख्या बढ़कर 1.72 लाख और 2024 में लगभग 1.88 लाख तक पहुँच गई। अर्थात् प्रतिदिन पाँच सौ से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि बलाघोष परियों के उजड़ने और समाज की अप्रुणीय क्षति की कहानी है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता संकट केवल यातायात व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ अंधकार है। हर दुर्घटना के पीछे कई कारण काम करते हैं, जिनमें चालक की लापरवाही,

विकास की चमक के पीछे बिखरती ज़िंदगियों का सच

यातायात नियमों का उल्लंघन, खराब सड़कें, अपर्याप्त निगरानी और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था प्रमुख हैं। देश में मोटर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में सड़क सुरक्षा की संस्कृति विकसित नहीं हो सकी है। लोग हेलमेट और सीट बेल्ट को सुरक्षा उपकरण की बजाय पुलिस चालान से बचने का माध्यम मानते हैं। परिणामस्वरूप छोटी-सी चूक भी कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाती है। सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज गति है। आधुनिक राजमार्गों और चौड़ी सड़कों ने वाहनों की गति तो बढ़ा दी है, लेकिन जिम्मेदार ड्राइविंग की भावना उतनी विकसित नहीं हुई। युवा वर्ग में विशेष रूप से तेज गति से वाहन चलाने को रोमांच और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा है। सोशल मीडिया पर स्टंट और रेसिंग के वीडियो इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देते हैं। जब वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलता है, तब चालक के पास प्रतिक्रिया देने का समय कम हो जाता है और दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं का एक गंभीर कारण है। कानून इसके विरुद्ध कठोर है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन हर जगह नहीं हो पाता। कई बार देर रात होने वाली दुर्घटनाओं में पाया गया है कि चालक नशे की अवस्था में था। नशा व्यक्ति की निर्णय क्षमता और प्रतिक्रिया समय दोनों को प्रभावित करता है, जिससे दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। इसी प्रकार मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना भी आधुनिक समय की एक बड़ी चुनौती बन गया है। बातचीत, संदेश सड़क या सोशल मीडिया देखने में चालक सड़क से

हट जाता है और कुछ ही सेकंड की असावधानी घातक सिद्ध हो सकती है। सड़कों की भौतिक स्थिति भी इस संकट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। देश में अनेक स्थानों पर सड़कें गड्ढे से भरी हुई हैं, संकेतक बोर्डों का अभाव है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अपर्याप्त है तथा मोड़ों और चौराहों पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई दुर्घटनाएँ सीधे तौर पर सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता और रखरखाव की कमी से जुड़ी होती हैं। यदि सड़कें सुरक्षित और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप बनाई जाएँ तो दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। देश में पूरे वर्ष चुनौती रैलियों, सार्वजनिक सभाएँ, रोड शो और विभिन्न बड़े आयोजन होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है। परिणामस्वरूप यातायात नियंत्रण के लिए उपलब्ध मानव संसाधन कम पड़ जाते हैं। कई स्थानों पर राजमार्गों और व्यस्त सड़कों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। इससे नियमों का पालन कमजोर होता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यह स्थिति बताती है कि सड़क सुरक्षा को केवल पुलिस का विषय मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए अलग और सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटनाओं का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक है। विश्व बैंक की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा नुकसान के रूप में भुगतान पड़ता है।

भारत में भी हर वर्ष लाखों लोग घायल होते हैं, जिनके उपचार पर भारी खर्च आता है। अनेक परिवारों का एकमात्र कमाने वाला सदस्य दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो जाता है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट में फँस जाता है। विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति की आय क्षमता प्रभावित होती है और समाज पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाएँ केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए भी बाधा हैं। सड़क सुरक्षा के सामाजिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। दुर्घटनाओं में मरने वालों का बड़ा हिस्सा युवाओं का होता है, जो देश की कार्यशील आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई युवा असमय मृत्यु का शिकार होता है, तो उसके साथ अनेक सपने और संभावनाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। परिवार मानसिक आघात से गुजरता है और बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए सड़क सुरक्षा को जनस्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के मुद्दे के रूप में भी देखा जाना चाहिए। समस्या का एक बड़ा कारण यातायात नियमों के प्रति समाज का उदासीन रवैया भी है। अक्सर लोग लाल बत्ती पार करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग करना और बिना लाइसेंस वाहन चलाना सामान्य बात समझते हैं। जब नियमों का उल्लंघन सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार बन जाता है, तब कानून अकेले प्रभावी नहीं हो सकता। इसके लिए जन-जागरूकता, नैतिक शिक्षा और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा का पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जा सकें। सरकार ने हाल के वर्षों

में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्मानों को बढ़ाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था की जा रही है तथा 'गुड समैरिटेन' जैसी नीतियों के माध्यम से दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं क्योंकि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता में अभी भी कमी बनी हुई है। वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं की समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण में निहित है। सुरक्षित सड़कें, प्रशिक्षित चालक, कठोर कानून, आधुनिक तकनीक, पर्याप्त यातायात कर्मियों, त्वरित चिकित्सा सहायता और जागरूक नागरिक, इन सभी की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। साथ ही, चुनौती रैलियों, बड़े सार्वजनिक आयोजनों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के बीच भी यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा को विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार करना होगा। अब यह समझना होगा कि सड़क दुर्घटनाएँ भाग्य या संयोग का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि अधिकांश मामलों में वे मानवीय भूलों और व्यवस्थागत कमियों का नतीजा होती हैं। यदि सरकार, प्रशासन और नागरिक समाज मिलकर जिम्मेदारी निभाएँ तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। विकास केवल तेज सड़कें बनाने से नहीं, बल्कि उन सड़कों पर लोगों को सुरक्षित घर पहुँचाने से सिद्ध होता है। जब तक भारत अपनी सड़कों को सुरक्षित नहीं बना लेता, तब तक विकास की चमक के पीछे बिखरती ज़िंदगियों का यह दर्दनाक सच हमारे सामने खड़ा रहेगा।

दूरिकोण

ब्रजेश कानूनगो

लेखक संतंकार हैं।



इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक एंकर के बयान ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को उद्विग्न कर दिया। इस नए विवाद से शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों, मीडिया के रवैए और भाषा को लेकर नई बहस खड़ी हो गई है। दरअसल यह विषय केवल एक टीवी एंकर के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, मीडिया, कोचिंग उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श की भाषा से जुड़े व्यापक प्रश्नों को सामने लाता है। इस विवाद ने यह सोचने का अवसर दिया है कि समाज में शिक्षकों की भूमिका, ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता तथा मीडिया की जिम्मेदारी को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंकर की टिप्पणी ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों और कोचिंग जगत में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध के स्वर तेज हुए, जिससे शिक्षा और मीडिया के संबंधों पर एक नई बहस शुरू हो गई। यह विवाद केवल किसी एक व्यक्ति के कथन का मामला नहीं है, बल्कि उस बदलते सामाजिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है जिसमें डिजिटल शिक्षा, कोचिंग उद्योग और मीडिया तीनों महत्वपूर्ण भूमिका

निभा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षकों का मानना है कि उन्होंने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम लागत पर उपलब्ध हुई है। दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण कई बार एकमात्र व्यवहारिक विकल्प बनकर उभरा है। ऐसे में यदि किसी टिप्पणी में पूरे ऑनलाइन शिक्षण समुदाय को संदेह या उपहास की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षक इसे अपने पेशे और सम्मान पर आघात के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि कुछ अपवादों के आधार पर पूरे समुदाय का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। दूसरी ओर, कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायीकरण तेजी से बढ़ा है। अनेक प्लेटफॉर्म और कोचिंग संस्थान आक्रामक विज्ञापन, अवास्तविक

सफलता के दावे तथा विद्यार्थियों की भावनाओं के व्यावसायिक उपयोग के आरोपों का सामना करते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि मीडिया इन प्रवृत्तियों पर सवाल उठाता है तो इसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शिक्षक सम्मान की भावना। यह विवाद कोचिंग संस्कृति पर भी ध्यान आकर्षित करता है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती संख्या और रोजगार की सीमित संभावनाओं ने कोचिंग उद्योग को विशाल आकार दिया है। कई संस्थानों ने उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है, लेकिन कुछ स्थानों पर अत्यधिक शुल्क, सफलता का दावा और आक्रामक मार्केटिंग जैसे प्रश्न भी उठते रहे हैं। इसलिए बहस का एक पक्ष यह भी है कि शिक्षा सेवा है या व्यवसाय? संभवतः वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं स्थित है,

जहाँ गुणवत्ता और आर्थिक स्थिरता दोनों का संतुलन आवश्यक है। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व प्रश्न पूछना और सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठाना है। यदि शिक्षा क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसकी जांच-पड़ताल और आलोचना मीडिया का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। किन्तु दूसरी ओर मीडिया से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह आलोचना करते समय तथ्यों, संतुलन और मर्यादा का पालन करे। किसी पूरे वर्ग को एक ही तराजू में तोलना या उतेजक भाषा का प्रयोग करना संवाद के बजाय टकराव को जन्म देता है। समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता इसी बात पर निर्भर करती है कि वे आलोचना और सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखें। इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का है। सार्वजनिक जीवन में शब्द केवल विचार व्यक्त नहीं करते, बल्कि सामाजिक वातावरण की निर्मित करते हैं। मीडिया,

राजनेता या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के वक्तव्य लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन उसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। कठोर आलोचना संभव है, परंतु व्यक्तिगत आक्षेप, अपमानजनक शब्दावली या किसी पेशे के सामूहिक अवमूल्यन से बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस तथ्यों और तर्कों पर आधारित होती है, न कि कटुता और सनसनी पर। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सही मार्गदर्शन और विश्वसनीय जानकारी चाहिए। उनके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, कोचिंग संस्थान और मीडिया-तीनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं। विद्यार्थी न तो अंधभक्ति चाहते हैं और न ही निराधार आरोपों की राजनीति। वे ऐसे वातावरण की अपेक्षा करते हैं जिसमें शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और क्षमता निर्माण हो,

न कि केवल विवाद और प्रचार। ऑनलाइन शिक्षकों और मीडिया के बीच उभरा यह विवाद किसी एक बयान से कहीं बढ़ा है। ऐसे विवादों से कई उपेक्षित संदर्भ और मुद्दे चर्चा में आते हैं। इस विवाद ने भी शिक्षा के व्यवसायीकरण, डिजिटल शिक्षण की उपयोगिता, मीडिया की जवाबदेही और सार्वजनिक संवाद की भाषा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने ला दिया है। जो कि एक लोकतांत्रिक देश और उसके नागरिकों के लिए सुखद ही कहा जाएगा। एक संतुलित दृष्टिकोण यही कहता है कि न तो सभी ऑनलाइन शिक्षकों को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और न ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वैध प्रश्नों को उठाने पर रोक लगानी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि आलोचना तथ्यपरक हो, भाषा संयमित हो और संवाद सम्मानजनक हो। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान परस्पर सम्मान और विवेकपूर्ण चर्चा से ही संभव है।

विचार

श्याम बोहरे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



अतिशयोक्ति को पसन्द या न पसन्द करना इस बात पर निर्भर करता है कि वह तारीफ में की गई या निंदा में? यूँ तो सभी क्षेत्रों में अतिशयोक्ति का बोलबाला है, अपने सीमित शिक्षकीय अनुभव में मुझे शिक्षकीय महानता के जो भी दर्शन हुए, उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो कम से कम सच के नजदीक तो नहीं कहा जा सकता। शिक्षक दिवस पर शिक्षक साथियों से शिक्षकीय महानता सुन सुन कर और कुछ समझ में आया हो या न आया हो, महानता शब्द का अर्थ गडगुड जरूर हो गया है।

शिक्षकीय महानता को एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करते हैं। मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्यापक था। एक दिन स्टाफ रूम, जहां अपने खाली समय में हम शिक्षक बैठते थे, में काफ़ी विषय का छत्र आया और सभी अध्यापकों के पैर छूते हुए उनका

शिक्षकीय महानता को एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करते हैं। मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्यापक था। एक दिन स्टाफ रूम, जहां अपने खाली समय में हम शिक्षक बैठते थे, में काफ़ी विषय का छत्र आया और सभी अध्यापकों के पैर छूते हुए उनका आशीर्वाद लेने लगा। जिस तरह मन्दिर में भगवान प्रणाम करने वाले भक्तों से उनका नाम और परिचय नहीं पूछते उसी तरह पर पड़वाने वाले अध्यापकों को भी उस छत्र का नाम परिचय आदि जानने में कोई रुचि नहीं थी। लगभग अंत में वह मेरे पास आया और पैर छुए। चूँकि मैं उसे जानता नहीं था इसलिए उसका नाम पूछा और जानना चाह कि किस विषय का और कौन सी कक्षा में पढ़ता है, मेरे पैर क्यों छू रहा है? इस तरह से उसका परिचय जानना चाहता था। यह भी कि जिसे मैं जानता नहीं वह भला लड़का मेरे पैर क्यों छू

रहा था? उसने बताया कि सर आपके आशीर्वाद से पास हो गया हूँ, इसलिए। शिक्षकीय पाखण्ड में रचा-बसा नहीं होने के कारण मैंने चौंके हुए पृष्ठ कि मैं तुम्हें जानता नहीं तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कैसे मिला? क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है? परीक्षा में नकल करवाई? कोई पेपर आउट कराया? तुम्हारे नम्बर बढ़वाए? सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में ही था। तब मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास होने में मेरी कोई भूमिका नहीं है तो यह बताओ अपनी मेहनत से पास हुए या मेरे आशीर्वाद से? तुमने मेहनत

की या नहीं? उसने कहा कि सर मेहनत तो की है। तब मैंने कहा कि सुनो तुम्हें जिन अध्यापकों ने पढ़ाया है उन्होंने भी कोई मेहरबानी नहीं की। उन्होंने जितना पढ़ाया उसका पैसा सरकार ने उन्हें दिया है। नौजवान हो अपनी काबलियत पर भरोसा करना सीखा। दूसरों का मैं नहीं कह सकता लेकिन यह जानता हूँ कि तुम्हारे पास होने में मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है। तुमने अपात्र के पैर छूकर गलती की है, भविष्य में नहीं करना। उस छत्र के जाते ही वहां मौजूद अध्यापक साथियों ने जमकर मेरी धुलाई की। यह सब बकवास करने का

क्या मतलब था? वह संस्कारी छत्र है, आप तो कुछ समझते नहीं हैं। उस बालक को संस्कारों से क्यों भटकना चाहते हो? समाज में वैसे ही शिक्षकों की इज्जत कम होती जा रही है, आपको इन हरकतों से और कम हो जायेगी।

मैंने कहा कि यदि इस पाखण्ड को आप इज्जत मानते हो तो कल नष्ट होती हो तो आज और अभी हो जाए। थोड़ी देर बहस हुई, तभी एक साथी अध्यापक ने कहा कि दरअसल बात यह है कि इतना सच बोलने-सुनने की हमारी आदत नहीं है। बहस को पूर्णविराम उनके इस वाक्य से लगा कि इस मामले में चुप रहने में ही भलाई है, वरना जितनी बहस करोगे उतने ही कपड़े उतरते जायेंगे। उन अध्यापक महोदय ने मुझे भी सीख देते हुए कहा, आपको भी यह गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि आप इस तरह के पाखण्ड से शिक्षक समुदाय को और समाज को दूर कर सकते हो। एक साथ इतने अधिक दुश्मन बनाकर कैसे रहोगे भाई? मैं भी सरकारी नौकर ही था कोई विचारक या क्रांतिकारी तो था नहीं इसलिए सुविधाजनक और सुरक्षित रास्ता जल्दी समझ में आ जाता था।

भारत विश्व की चार बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में शामिल रक्षा क्षेत्र में भी बढ़ी ताकत: कैलाश विजयवर्गीय

प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, जिला भाजपाध्यक्ष निलेश भारती शामिल हुए

धार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को जिला कार्यालय में विकसित भारत प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में चिकित्सा, शिक्षा, विधि, व्यापार, प्रशासन एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे।

केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु राठौड़ व मनोज सोमानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तागंवा, पूर्व विधायक वेलसिंह भूरिया, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ महाजन, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश राजपुरोहित, समाजसेवी योगेश अग्रवाल, रेखा मेहता अतिथि रूप में मंचासीन थे।

भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने स्वागत उद्घोषण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर निरंतर नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। हम सभी मोदी सरकार के ऐतिहासिक 12 साल के कार्यकाल के बारे में आम जनता को बताएँ। अतिथियों ने भारत माता व पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मध्यप्रदेश शासन के



कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की दिशा तय करने में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षित, जागरूक और विचारवान लोगों के मार्गदर्शन से ही देश विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।

विजयवर्गीय ने कहा कि भारत आज विश्व की

चार बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में अपना स्थान बना चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत अधिकांश आवश्यक सामग्रियों का आयात करने वाला देश था, लेकिन आज देश निर्यातक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और रक्षा सौदों तथा सैन्य क्षमताओं के मामले में भारत विश्व की बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ रहा था

भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्धजनों से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनकी लंबे समय से अपेक्षा की जा रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ..

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन के पूर्व में भाजपा जिला कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की विकास यात्रा पर प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य वक्ता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने, राकेश पटेल, संजय बघेल डॉ शरद विजयवर्गीय, अशोक जैन, लव प्रजापति, अभियान जिला टोली से कपिल निनामा, अमृत पाटीदार, पिपूष सोनगरे, रोमा मंडलेंडी मौजूद रहें। संचालन भाजपा के जिला पदाधिकारी मोहित तितेड़ व आभार जिला टोली के रिशे आनिहोत्री ने माना।

जिला चिकित्सालय में जागरूकता, परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

बैतूल। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बैतूल में शुक्रवार को सिकल सेल एनीमिया के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, रोगियों को परामर्श प्रदान करने तथा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देना तथा नागरिकों को सुख पर जांच एवं उपचार के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उखेके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सहभागिता की। अतिथियों ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जिले में संचालित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की तथा उपस्थित नागरिकों को जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. अंकिता सीते द्वारा बैतूल जिले में संचालित सिकल सेल निर्यंजन एवं उन्मूलन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।



उन्होंने जिले में अब तक किए गए स्क्रीनिंग कार्य, रोगी पहचान, फॉलोअप व्यवस्था, उपचार सेवाओं तथा जनजागरूकता गतिविधियों की उपलब्धियों से अतिथियों को अवगत कराया। इस अवसर पर सिकल सेल की त्वरित एवं सटीक जांच में उपयोगी गैजल मशीन का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों ने मशीन की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर इसकी उपयोगिता की सराहना की। विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल एवं डॉ. योगेश पंडाग्रे ने अपने-अपने

विधानसभा क्षेत्रों में सिकल सेल जांच सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विधायक निधि के माध्यम से गैजल मशीन उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। शिविर के दौरान 61 सिकल सेल रोगी फॉलोअप एवं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपस्थित हुए, जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श, आवश्यक जांच एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। रोगियों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, दवा सेवन,

टीकाकरण तथा जटिलताओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी दी गई।

सिकल सेल उन्मूलन अभियान में युवाओं एवं समाज की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 5 सिकल मित्र नामित किए गए। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स को भी सिकल मित्र के रूप में जोड़ते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में सिकल सेल जागरूकता, स्क्रीनिंग तथा विवाह पूर्व सिकल सेल कार्ड मिलान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में डॉ. अरुण जयसिंहपुरे, राजेश आहूजा, सिकल सर्जन डॉ. जगदीश घारे, आरएमओ डॉ. रानू वर्मा, डॉ. अंकिता सीते सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

विशेष शिविर में सिकल सेल एनीमिया की जांच, रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श तथा जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सिकल सेल रोग की पहचान, समय पर उपचार, नियमित जांच एवं अनुवांशिक परामर्श के महत्व पर जानकारी दी गई।

शास. भोज कन्या विद्यालय से साधना रावल-किरण राठौड़ हई सेवानिवृत्त, स्टाफ ने दी विदाई



धार। शासकीय भोज कन्या उच्चतर विद्यालय धार में विगत 39 वर्षों से संस्कृत विषय की अध्यापक के रूप में सेवा देकर साधना रावल सेवा निवृत्त हुईं साथ ही शिक्षिका किरण राठौड़ ने 42 वर्षों से सामाजिक विज्ञान में सेवा देकर कर अपना फर्ज पूरा किया। इस शुभ अवसर पर भोज कन्या परिवार द्वारा उन्हें फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया व प्रशस्ति पत्र भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। सहकर्मियों ने उनके योगदान को सराहा और उनके उज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस मौके प्राचार्य आर पी पांडे, नीता जैन खीरद जैन, राजेश वर्मा विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक उपस्थित रहे संचालन प्रीति तिवारी व माधवी मुखर ने किया। मौके पर सेवानिवृत्त दोनों अध्यापिकाओं ने विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया

जिला स्तरीय रोजगार मेले में 112 विद्यार्थियों का हुआ चयन

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सप्लोरेशन, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अटल सभागार में युवा संगम 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला प्रशासन, जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई बैतूल तथा स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ बैतूल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिविर में 236 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें 96 छात्राएं एवं 140 छात्र शामिल थे। रोजगार मेले में प्राथमिक रूप से 112 विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष घनश्याम मदान ने युवाओं को स्वरोजगार की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि युवाओं को केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार प्रदान करने वाला बनना चाहिए।

59 बेसहारा बच्चों का सहारा बने हेमंत खंडेलवाल

विजय सेवा न्यास ने फीस और आर्थिक मदद से बच्चों का भविष्य संवारा

बैतूल। बैतूल- हर्दा क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल की स्मृति में संचालित विजय सेवा न्यास के माध्यम से 41 परिवारों के 59 बेसहारा बच्चों के जीवन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल सहारा बनकर सामने आए हैं। उनके द्वारा इन बच्चों की शिक्षा, परवरिश और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी उठाई जा रही है। शुक्रवार 19 जून को रामकृष्ण बरगिया में आयोजित कार्यक्रम में विजय सेवा न्यास द्वारा गोद लिए गए 59 बच्चों की स्कूल फीस के चेक संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों को सौंपे गए। साथ ही प्रत्येक बच्चे को शैक्षणिक सामग्री के लिए दो हजार रुपए तथा उनके पालकों एवं परिजनों को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता अलग से प्रदान की गई। यहां उल्लेखनीय है कि विजय सेवा न्यास के शुरुआती दौर में ही अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया है। इन बच्चों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि परित्याग के सदस्य की तरह शिक्षा, मार्गदर्शन और सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में 41 बच्चों के साथ



शुरू हुआ यह अभियान एक वर्ष में बढ़कर 59 बच्चों तक पहुंच गया है।

इन स्कूलों में करवाया प्रवेश... हेमंत खंडेलवाल ने बच्चों और उनके पालकों की सहमति तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए निजी एवं शासकीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलवाया है। विजय सेवा न्यास उनकी शिक्षा का पूरा खर्च वहन कर रहा है। एनडीएम हायर सेकेंडरी स्कूल शोभापुर, मानसरोवर स्कूल, विद्या संस्कार स्कूल, विद्यार्थी पब्लिक स्कूल, आरडी पब्लिक

स्कूल, अग्रसेन महाराज स्कूल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बच्चों का प्रवेश कराया गया है, जबकि अन्य बच्चों को शासकीय विद्यालयों में दाखिला दिलाया गया है। इस पहल में समाज भी सहभागी बना है। डॉन बास्को और लिटिल फ्लावर स्कूल को छोड़कर अधिकांश निजी विद्यालयों ने इन बच्चों की फीस का 25 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।

बच्चे को परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े: हेमंत खंडेलवाल

इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी बच्चे को परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं पड़े। उनका प्रयास है कि इन बच्चों को केवल सहायता ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन का अवसर भी मिले। इसी सोच के तहत बच्चों को परवरिश कर रहे परिजनों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में यह रहे मौजूद-

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उखेके, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, भैरवदेवी विधायक महेंद्र सिंह चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विजय सेवा न्यास के सेवा कार्यों की सराहना की। वक्तवाओं ने कहा कि स्व. विजय कुमार खंडेलवाल के मानव सेवा ही माध्यम से वै के विचारों को उनका परिवार सेवा अभियान के रूप में आगे बढ़ा रहा है।

धरमपुरी विधायक ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में जनकल्याण एवं शिकायत निराकरण शिविर आयोजित

106 आवेदन प्राप्त, 60 का मौके पर हुआ निराकरण

नालछ (धार)। जिले के समस्त विकासखंडों में आयोजित तीन दिवसीय जनकल्याण एवं शिकायत निराकरण शिविर के अंतर्गत गुरुवार को नालछ जनपद पंचायत क्षेत्र के मोगराबाव में खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम धरमपुरी विधायक कालूसिंह ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

विधायक कालूसिंह ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं विकास को समर्पित रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी जनहित एवं विकास के संकल्प के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितशाली तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नालछ मंडल अध्यक्ष रघु निनामा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 'सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण' के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। जनकल्याण एवं शिकायत निराकरण शिविर शासन एवं जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने नागरिकों से शासन की जनहितकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया।

जनपद उपाध्यक्ष दिलीप डबर, जनपद सदस्य पवन कुशवाह, मंडल महामंत्री विनोद ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 106 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 60 आवेदनों का त्वरित निराकरण मौके पर ही किया गया। शेष



आवेदनों को नियमानुसार संबंधित विभागों को समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार विशाखा चौहान, ग्राम पंचायत मोगराबाव संचालक सविता रघु निनामा, विधायक प्रतिनिधि अशोक मिरदवाल व डॉ. महेश यादव, जनपद सदस्य प्रभु बारिया व गोकुल गिरवाल, जौरापुरा सरपंच कैलाश मावी सहित ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप डबर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी। संचालन राजेश राठौड़ (शिक्षक) द्वारा किया गया। सभी को नशामुक्ति के लिए शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम के अंत में निखिल ग्वाल द्वारा सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपस्थित ग्रामीणजनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

धार के प्रतिभाशाली पार्थ सोनी प्रथम प्रयास में बने सीए, बढ़ाया मान

पार्थ धार के प्रसिद्ध आयकर अधिवक्ता गोपाल सोनी के सुपुत्र हैं

धार। धार शहर के युवा प्रतिभासंपन्न पार्थ सोनी ने कठोर परिश्रम और जुनून के दम पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा घोषित सीए फायनल की परीक्षा प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण कर सीए की डिग्री प्राप्त कर धार शहर का मान देश और प्रदेश में बढ़ाया है। अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा माता-पिता और परिवारजनों को देते हुए पार्थ ने बताया कि वे अपनी सफलता के प्रति आभार व्यक्त हैं। पार्थ सोनी धार के प्रसिद्ध आयकर अधिवक्ता व श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज धार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोपाल सोनी के पुत्र हैं। पार्थ सोनी की इस उपलब्धि पर शुभचिंतकों, मित्रों ने उन्हें बधाई दी।



संक्षिप्त समाचार

अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्यवाही

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पथाड़ा स्थित नर्मदा नदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध उत्खनन करते एक पनडुब्बी को जप्त किया गया। जप्त पनडुब्बी को पुलिस थाना सिवनी मालवा की अभिरक्षा में रखा गया है। संबंधित अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिप्रसन्न कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध सतत निगरानी एवं सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला शुद्ध पेयजल जांच का प्रशिक्षण

हरदा (निप्र)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा द्वारा सोमवार को मांदला सेक्टर में जल गुणवत्ता निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फील्ड टैस्टरिंग किट के माध्यम से शुद्ध पेयजल की जांच करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें फील्ड टैस्टरिंग किट का वितरण भी किया गया।

बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सीहोर में बिजली अधिकारियों की बैठक

सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (सतकर्ता) श्री डी.पी. अहिरवार एवं महाप्रबंधक श्री डी.के. धुर्वे द्वारा सीहोर में बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं पर बकाया राशि की वसूली, एम.पी.ई.आर.सी. एवं विद्युत उपभोक्ताओं पर बनाये गये गलत पंचनामों व कोर्ट केस के निपटान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही सतकर्ता के अंतर्गत बनाये गये प्रकरणों की राशि की वसूली की वृद्धि हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में महाप्रबंधक श्रीमती पूनम तुमराम सहित वृत्त के समस्त उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक उपस्थित थे।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर शिविर लगाकर किया गया 1074 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं एवं अनेक स्थानों पर प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत जिले में 16 जून को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 710 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 364 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 200 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

विभागीय उपलब्धियों की सफलता की कहानियां जनसंपर्क विभाग को भेजें: कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में सभी विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों तथा नवाचारों पर आधारित उपलब्धियों को रेखांकित करने वाली सफलता की कहानियां नियमित रूप से जनसंपर्क विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों से आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को प्रभावी ढंग से सामने लाना आवश्यक है। इसके लिए विभाग ऐसे हितग्राहियों, नवाचारों और विकास कार्यों की जानकारी संकलित करें, जिनसे समाज में उल्लेखनीय परिवर्तन आया हो। इन सफलता की कहानियों के माध्यम से शासन की योजनाओं के प्रभाव और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय स्तर पर उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण कर समग्र रूप से जनसंपर्क विभाग को भेजा जाए, ताकि उन्हें विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए आमजन तक पहुंचाया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि सफलता की कहानियां प्रेरणादायक होने के साथ-साथ तथ्यात्मक और प्रमाणिक भी हों, जिससे अन्य लोग भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित हो सकें। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिला जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) को निर्देश दिए कि प्रत्येक समय-समय (टीएल) बैठक में विभागवार प्राप्त सफलता की कहानियों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इससे यह समीक्षा की जा सकेगी कि कौन-कौन से विभाग अपनी उपलब्धियों और नवाचारों का प्रभावी दस्तावेजीकरण कर रहे हैं तथा किन विभागों को इस दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर

समस्याओं का हुआ ऑन-द-स्पॉट समाधान, खुशी-खुशी घर लौटे हितग्राही

विदिशा (निप्र)। नटेरन जनपद पंचायत व शमशाबाद निकाय का संयुक्त मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के तीसरे दिन भी हितग्राहियों का उत्साह देखते ही बना। नटेरन जनपद पंचायत के सभागार परिसर में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों के स्टालों पर बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। आज के शिविर में कुल 380 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 230 मामलों का मौके पर ही संवेदनशील और त्वरित निराकरण कर दिया गया। शेष बचे आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर समय-समय में निराकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मौके पर ही समस्याओं का समाधान पाकर दूर-दराज से आए आवेदक बेहद खुश नजर आए। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) अजय प्रताप सिंह पटेल पूरे समय शिविर में मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों को बेहद सहानुभूतिपूर्वक सुना और सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।

समापन सत्र में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

शिविर के समापन सत्र में एसडीएम अजय प्रताप सिंह पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि यशपाल सिंह खुबशी, जनपद सदस्य अंशुज प्रसाद शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष निरंजन सिंह खुबशी सहित नटेरन और शमशाबाद के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विभिन्न



विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पमारिया की निवासी गिरजा मीणा को 'एक बगिया मां के नाम' अभियान के अंतर्गत अपनी बगिया को उत्कृष्ट तरीके से विकसित करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही शिविर में कई हितग्राहियों को जाति प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।

शिविर की 3 बड़ी 'सफलता की कहानियां'

शिविर में प्रशासनिक मुस्तेदी के चलते कई चेहरों पर

मुस्कान लौटी। इनमें से तीन प्रमुख सफलता की कहानियां इस प्रकार हैं:

मिनटों में बना श्रुति पाल का आयुष्मान कार्ड, जताया आभार

बम्होरी (तहसील शमशाबाद) की निवासी श्रुति पाल पिछले काफी समय से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए परेशान थीं। शिविर में आयुष्मान कार्ड के स्टाल पर तैनात कर्मचारी राजकुमार और राहुल विश्वकर्मा ने एसडीएम के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए मिनटों में श्रुति का आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें सौंप दिया।

सिमरन के आधार कार्ड में सुधरी

जन्मतिथि, अब मिलेगी छात्रवृत्ति

नटेरन के सांदिपन शासकीय स्कूल में कक्षा 11 वीं (कला संकाय) की छात्रा सिमरन कुशवाह निवासी नटेरन भी अपनी समस्या लेकर शिविर पहुंची थीं। सिमरन के आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत दर्ज थी, जिसके कारण उनकी 'अपार आईडी' नहीं बन पा रही थी और छात्रवृत्ति सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ रही थी। आधार कैंप के स्टाल पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल सिमरन के दस्तावेज देखकर उनके आधार कार्ड में जन्मदिनांक को संशोधित किया। काम चुटकियों में होने पर सिमरन ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

प्रेमसिंह धाकड़ को पशुपालन लोन का स्वीकृति पत्र मौके पर मिला

डंगरवाड़ा (तहसील शमशाबाद) के निवासी प्रेमसिंह धाकड़ पशुपालन विभाग के स्टाल पर पहुंचे और 'आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना' के तहत आवेदन किया। स्टाल पर उपस्थित कर्मचारियों ने मौके पर ही उनके आवेदन को मंजूरी दी। यहीं नहीं, शिविर में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शमशाबाद के अधिकारियों ने तुरंत लोन स्वीकृत कर स्वीकृति पत्र प्रेमसिंह के हाथों में सौंप दिया। इस योजना के तहत अब प्रेमसिंह सखिडी का लाभ लेकर अपने रोजगार को और बढ़ा कर सकेंगे। अचानक मिली इस बड़ी सफलता से प्रेमसिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक बेहद प्रभावी और मील का पत्थर साबित रहा है।

श्रुति पाल ने कहा: 'मैं बहुत दिनों से परेशान थी और मेरा कार्ड नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज यहाँ मिनटों में काम हो गया। यह योजना सचमुच गरीबों के लिए वरदान है, जिससे हम निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मैं शासन-प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।'

साहस, त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है महाराणा प्रताप का जीवन: राजस्व मंत्री

महाराणा प्रताप जयंती पर प्रतिमा का अनावरण एवं मलय चल समारोह आयोजित

सीहोर (निप्र)। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सीहोर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण एवं भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। पावर हाउस चौराहा स्थित कार्यक्रम स्थल पर आयोजित समारोह में राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा एवं श्री कार्तिकेय चौहान ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर नगर में भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में महाराणा प्रताप के जीवन एवं शौर्य को दर्शाती झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस अवसर पर विधायक श्री सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर भी शामिल हुए।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और संघर्ष के मार्ग पर अडिग रहे। उनका जीवन साहस, त्याग,

भारतीय इतिहास के महानायक हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप



पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप की

गौरवगाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि महारूपों के जीवन से प्रेरणा लेकर ही समाज और राष्ट्र का सशक्त निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास में सक्रिय योगदान दें। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने भी संबोधित किया।

जनकल्याण शिविर से मिली नई राह, छात्र राजीव को मिला जाति प्रमाण पत्र

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत नटेरन जनपद कार्यालय के सभागार में आयोजित जनकल्याण शिविर ने खेजड़ा काशीराम ग्राम के छात्र राजीव जाटव के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। लंबे समय से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होने के बावजूद विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जनकल्याण शिविर की जानकारी मिलने पर छात्र राजीव ने वहां आवेदन किया। शिविर में अधिकारियों द्वारा त्वरित एवं सरल प्रक्रिया के माध्यम से उनका आवेदन स्वीकार किया गया और उन्हें वहीं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र



मिलने पर राजीव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे समय और

धन दोनों की बचत हो रही है। छात्र राजीव के अनुसार, जनकल्याण शिविर आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत कर रहा है।

जनकल्याण शिविर बना आधार संशोधन का सरल माध्यम

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में आयोजित जनकल्याण शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभर रहे हैं। नटेरन जनपद कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनकल्याण शिविर में आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं का निराकरण सहज और सरल तरीके से किया गया। कई नागरिकों के आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि एवं अन्य आवश्यक संशोधन बिना किसी परेशानी के मौके पर ही कर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों को पहले आधार संशोधन के लिए दूर-दराज के केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। लेकिन जनकल्याण शिविर के माध्यम से यह सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से उन्हें बड़ी राहत मिली। शिविर में गायत्री बाई, विक्की प्रजापति, आनंद सहरिया, भावना, गनू लाल, विकास बंजारा, प्रवेश



कुशवाहा, जितेंद्र सेन, शक्तीला बी, वाहिद खां, प्रदीप दुबे, पानबाई और भुरी बाई सहित अनेक हितग्राहियों के आधार कार्ड में सफलतापूर्वक संशोधन किया गया। हितग्राहियों ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि शासन की यह पहल ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी है। उन्होंने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनकल्याण शिविरों से शासकीय सेवाएं अब लोगों के द्वार तक पहुंच रही हैं।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में नशा मुक्ति शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन

नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने और समाज को नशामुक्त बनाने का दिया गया संदेश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में नशा मुक्ति शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन आज रविन्द्र नाथ टैगोर संस्कृतिक भवन आडिटोरियम में किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग, उनके दुष्प्रभावों तथा अवैध व्यापार की रोकथाम के संबंध में जागरूक करना था।

विकसित भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक संस्था अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नशा मुक्त शिविर में उपस्थित नागरिकों को नशे के कारण होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को नशे से दूर रहने



तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों

और उनसे बचाव के उपायों को सरल एवं प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजंता

ललित कला समाज कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन प्रभावित होता है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए शासन, प्रशासन और समुदाय को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे।

उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के विभिन्न आयामों की जानकारी देते हुए अभियान से जुड़ने के लिए विकसित नए मोबाइल एप तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रारंभ की गई 'नशा मुक्त भारत मित्र' योजना के बारे में भी विस्तार से

बताया। उन्होंने नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने तथा स्वयं एवं अपने परिवार को नशे से दूर रखने की शपथ भी दिलाई गई। सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र के काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय विभाग की सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा तवर तथा श्रीमती मालती लोधी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नशे के विरुद्ध जनजागरूकता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर विशेष बल दिया गया।

राइट विलक

चढ़ावा चोरी : आस्था को बचाने 'डिजीटल अर्पणम्' अपनाएं !



अजय बोकिल

करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केन्द्र अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सवा साल से ज्यादा समय से चढ़ावा चोरी का जो बेखौफ खेल चल रहा था, उससे लगता है कि रामभक्तों से ज्यादा चढ़ावा चोरों को भगवान राम पर भरोसा था कि आस्था की जेब से निकले चढ़ावे की जी चाहें जितनी रकम डकारते जाओ, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मंदिर भी राम का, भक्त भी राम के, चढ़ावा भी राम का, चढ़ावा चोर राम के और चोर पकड़ने वाले कोतवाल भी रामके। अब सवाल तो यह है कि राम भक्त आखिर करें क्या? क्या चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें, हाथ जोड़कर दर्शन की इतिश्री कर लें या फिर चढ़ावे को बचाने के कुछ सुरक्षित तरीके अपनाएं जिस तरह इस भव्य मंदिर में भी चोरों का नेटवर्क सामने आया है, उसका सबक तो यही है कि मंदिर में अब श्रद्धालुओं को नकदी के बजाए जगह डिजीटल अर्पणम् (चढ़ाव) को ही तवज्जो देनी चाहिए। दानपेटियों को अब क्यूेदान में डाल दिया जाना चाहिए ताकि आस्था और विश्वास की पवित्रता कायम रखी जा सके। यूं भी आजकल लोग चाय-पान तक का पेमेंट भी यूपीआई से करते हैं तो भगवान की सेवा में आस्था के पत्रम् पुष्पम् के लिए यह तरीका ज्यादा सुरक्षित होगा। वैसे भगवान तो खुद दाता है, भक्त उसे भला क्या देगा। चढ़ावे के रूप में जो कुछ दान पुण्य किया जाता है, वह वास्तव में मंदिर के भौतिक रखरखाव और धर्म के प्रबंधन के लिए होता है। 21वीं सदी में भगवान से भी यही अपेक्षा है कि वो भक्त की दानशीलता का अकाउंट ऑन लाइन ही मॉटेन करें। डिजीटल दान का बड़ा लाभ यह है कि आपकी अटूट श्रद्धा पंडे पुजारी, नोट गणक अथवा प्रबंधकों की बुरी नजर से बची रहेगी। जो अभी भी डिजीटल फ्रेंडली नहीं हैं, वो दान काउंटर पर ही चढ़ावा देकर रसीद लें ताकि ट्रस्ट और बैंक की जानकारी में भी भगवान के हिसाब में रहे ताकि आखिर में पाप-पुण्य के ऑडिट के समय आपको वाञ्छित 'वेजेज' मिल सके। हालांकि मानवीय नीयत के आगे यह तरीका भी सौ फीसदी

सुरक्षित नहीं है। लेकिन उस दानपेटी में भोले मन से डाली गई नकदी से तो बेहतर ही है, जो गिनती के दायरे में आने से पहले ही अंटी कर ली जाती है। इस पूरे चढ़ावा कांड में आरंभिक जानकारी में पता चला है कि श्री राम मंदिर में रोजाना 5 करोड़ रू. का नकदी और सोने चांदी का चढ़ावा आ रहा था और इसमें से प्रतिदिन औसतन 10 लाख रू. पर चढ़ावा चोरी गैंग हाथ साफ कर रही थी। अब खबर है कि चढ़ावा चोरी कांड उजागर होने के बाद अब नकदी चढ़ावे की राशि घटकर डेढ़ करोड़ रू. प्रतिदिन पर आ गई है। हैरानी की बात यह है कि स्वयं भगवान के दरबार में हो रही? खुले आम चोरी को लेकर किसी के माथे पर कोई शिकन या आत्मग्लानि का भाव नहीं था, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट हो या मंदिर प्रबंधन अथवा सुरक्षाकर्मी। आरंभिक जांच में पुलिस ने 2.8 करोड़ की रकम जन्त भी की है।

यह भी विडंबना है कि राम भक्त जिस चढ़ावे को आध्यात्मिक मोक्ष की आकांक्षा से मंदिर में चढ़ाते रहे हैं, वही पैसा चढ़ावा चोरों की भौतिक समृद्धि और अय्याशी का कारण बन रहा है।

श्री राम मंदिर निर्माण में गड़बड़ियों की शिकायतें तो 37 साल पहले राम शिला पूजन अभियान से आने लगी थीं कि सोने की कई शिलाएं गायब हैं। इसमें कुछ व्यापारियों द्वारा दी गई हरेजड़ित शिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन तब इसे अफवाह या विघ्न संतोषियों की चाल मानकर दबा दिया गया था। फिर श्रीराम मंदिर जमीन अधिग्रहण मामले में भी भारी हेराफेरी की शिकायतें आईं। लेकिन उसे भी अनसुना कर दिया गया। यूं अब भारी हल्ला मचने के बाद यूपी सरकार ने तीन अफसरों की एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई प्रारंभिकी किसी के खिलाफ दर्ज नहीं है। की जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहां तक कि तीन रामभक्तों ने पुलिस में लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन उस पर भी पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लिया जाएगा भी नहीं, कहा जा

नहीं जा सकता। अलबत्ता एसआईटी की जांच के दौरान चढ़ावा चोरी के व्यापक नेटवर्क और ऊपरी वरदहस्त की जानकारीयां जरूर सामने आ रही हैं। सवाल उठता है कि क्या सारी व्यवस्था ही अंधी है?

शक की सुई श्रीराम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इर्द-गिर्द घूम रही है। हालांकि उन्हें बचाने वालों में से एक वरिष्ठ पदाधिकारी नृपेन्द्र मिश्रा का कहना है कि चंपत राय बेदाग हैं। लेकिन एक अदले से रामभक्त के मन में उठने वाले इन सवालों कि अगर चंपत या बेदाग हैं तो मंदिर में चढ़ावा चोरी का खेल इतने दिनों से कैसे चल रहा था, किसके संरक्षण में चल रहा था? चंपत राय को इसकी खबर कैसे नहीं लगी? लगी तो उन्होंने तत्काल इसे रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की? कहते हैं कि चंपत राय के बिना श्रीराम मंदिर में पता नहीं हिलता तो फिर उन्हें इतने बड़े घपले की हवा कैसे नहीं लगी? अगर उन्हें यह 'खुला रहस्य' भी पता नहीं था तो वो महासचिव के पद पर बैठ कर क्या रहे थे? अगर वो गॉफिल थे तो यह भी कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और नैतिक अपराध है। हो सकता है कि सपा नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे को न उठाते तो इस चढ़ावा चोरी पर पर्दा डला रहता और राम भक्त यूं ही ठगे जाते रहते। पहले भाजपा नेताओं और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों इसे खरिज किया। लेकिन जब संतों, कुछ पुराने विहिण नेताओं और भाजपा सांसदों ने ही चढ़ावा चोरी में घपले की बात उठानी शुरू की तो सरकार चेतनी। चढ़ावे की रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ के सहयोग से की जाती है। लेकिन एसबीआई भी इस मामले में मौन धारण किए रहा। अभी तक कुल कितनी राशि गबन की गई और किस किस की जेब में गई, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा।

श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा राजनीतिक रंग लेगा या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन इससे भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास में कमी जरूर आएगी। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन और इस मामले में आरएसएस की खामोशी पर

भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चंपत राय वहीं से आते हैं। संभव है कि संघ ने अंदरूनी तौर पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की हरी झंडी दे दी हो, लेकिन जो अभी तक सामने आया है, वह बहुत क्षोभजनक और लज्जास्पद है। इसका अंदाजा भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चढ़ावे में गबन करने वाले 'बहुत बड़े' लोग हैं। समय आने पर मैं उनके नाम उजागर करूंगा। इसका अर्थ यही है कि इस खेल में वो लोग भी शामिल हैं, जिनका नाम लेने में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे विवादित सांसद को भी 'डर' लगता है।

दरअसल इससे राम मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों के नैतिक चरित्र की कलई खुल गई है। श्रीराम के जिस मंदिर में भगवान राम के नैतिक आदर्श के अनुरूप ही सारा काम होना चाहिए था, उसी में सबसे पहले पलती लागया गया है। आदि ऋषि वाल्मीकि के 'रामायण' और गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में रामराज्य की व्याख्या ऐसे कल्याणकारी सुशासन के रूप में की गई है, जिसमें राज्य में लोगों में अपराध और लोभ का अभाव था। राज्य में कोई भी चोर या डकैत नहीं था। प्रजा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करती थी और किसी में लोभ या लालच नहीं था। कोई व्यक्ति सपने में भी पाप या अधर्म का आचरण नहीं करता। रामराज का मूलाधार लोगों की नैतिक उत्कृष्टता थी। राममंदिर के चढ़ावा घपले में इसी नैतिकता का निलंबन कल्ल हुआ है। आलम यह है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाला हर आस्थावान हिंदू चढ़ावा चढ़ाने के पहले दो बार सोचेगा कि यह किन हथों में जाएगा।

अब देखा जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद क्या और कैसी कार्रवाई होती है। दोषियों को कठोरतम दंड देकर रामभक्तों की भावनाओं के साथ न्याय किया जाएगा या फिर दो चार छुटभैयों को फंसाकर मामला रफा-फटा कर दिया जाएगा? यानी 'हुई है वही जो राम रचि राखा!'

नहर का पानी छोड़ने के लिए हाईवे पर घंटों चक्काजाम

200 से ज्यादा किसान बैलगाड़ियां लेकर पहुंचे, केले की फसल तबाह होने से तबीयत बिगड़ी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून की बेरखी और प्री-मानसून की मार ने किसानों को संकट में डाल दिया है। प्रदेश में मानसून की देरी के कारण जहां 1 जून से अब तक सामान्य से 39 प्रतिशत कम बारिश हुई है और खरीफ की बुवाई अटक गई है, वहीं बड़वानी में आई तेज आंधी-बारिश से केले की फसल तबाह हो गई। इससे एक किसान सदमे में आ गया। तबीयत खराब होने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर सूखे के इसी संकट के बीच खराब नहर से पानी छोड़ने की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह 11.30 बजे किसानों ने खंडवा-बड़ौदा हाईवे पर बैलगाड़ियां खड़ी कर चक्काजाम कर दिया, जो करीब 3 घंटे तक चला। एनवीडीए अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि नर्मदा के पिपलाई बैलेंसिंग रिजवायर-2 से हर छह दिन में पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद किसानों ने आंदोलन खत्म



कर दिया और दोपहर करीब 2:30 बजे यातायात बहाल हो सका। चक्काजाम के दौरान दोनों ओर

आवागमन को अनुमति दी गई।

200 से ज्यादा किसानों ने शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे खंडवा-बड़ौदा हाईवे पर बैलगाड़ी खड़ी कर चक्काजाम कर दिया। सभी लोग नहर का पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। जिले में कई किसान अब टोना-टोटका, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए बारिश में कामना कर रहे हैं। यहां के किसान चिरकुट पराड़कर बताते हैं कि मृग नक्षत्र शुरू हुए 13 दिन बीत चुके हैं। खेत जुताई के साथ तैयार हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से पैदावार प्रभावित हो रही है। जिले में अधिकांश किसानों ने खेतों की जुताई कर तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण अभी बुवाई शुरू नहीं हुई है। जिले में अधिकांश किसानों ने खेतों की जुताई, प्लेवा और नर्सरी तैयार कर ली है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से बुवाई और रोपाई का काम गति नहीं पकड़ पा रहा है।

9 एकड़ में केले की फसल जमीन पर बिछ गई

बड़वानी जिले के खड़की में मौसम की मार देखने को मिली। यहां तेज आंधी और बारिश ने दो किसान भाइयों अंबाराम और गंगाराम की 9 एकड़ में खड़ी केले की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया। बाजार में बिकने के लिए तैयार करीब 1500 पौधे जमीन पर बिछ गए। किसान भाइयों के मुताबिक, फसल पर 14 लाख की लागत आई थी और कुल 36 लाख का नुकसान हुआ है। इस भारी नुकसान के सदमे से किसान अंबाराम की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पीडित किसानों ने प्रशासन से तुरंत सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एम.ओ.एस.पी.आई एवं राज्य सरकार के मध्य सांख्यिकीय गतिविधियों के प्रभावी समन्वय एवं केंद्रीय क्षेत्रीय अक्संसंचना परियोजनाओं की निगरानी के समन्वय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उप महानिदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, (क्षेत्र संकाय प्रभाग) तथा सम्बंधित केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य के विभागों/केंद्रीय या राज्य पीएसयू के प्रतिनिधि (एजेंड अनुसार) सदस्य होंगे। आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र. को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम- राज्य स्तरीय समन्वय समिति का कार्यक्षेत्र एम.ओ.एस.पी.आई और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य के सांख्यिकी विभाग के बीच नियमित संवाद को सुगम बनाना जिससे प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षणों जैसे एन.एस.एस., ए.एस.एल., आर्थिक जनगणना एएसयूआई, पीएलएफएस, एचसीआईएस अलावा अन्य सांख्यिकी गतिविधियों का योजनाबद्ध क्रियान्वयन किया जा सके। आगामी अखिल भारतीय सर्वेक्षणों, संपन्न फेम, संपन्न मिलान तथा जलनों/राज्य की भागीदारी से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाना, एम.ओ.एस.पी.आई द्वारा जारी मानकों जैसे राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (एन.एम.डी.एस) 2.0, सांख्यिकी गुणवत्ता मूल्यांकन चंचा (एस.व्यू.ए.एफ) आदि के राज्य सांख्यिकी प्रणाली में अपनाना तथा समीक्षा एवं निगरानी करना तथा एम.ओ.एस.पी.आई तथा राज्य सरकार के सांख्यिकी विभाग के बीच समन्वय के लिए मंच के रूप में कार्य करने जैसे कार्य किए जाएंगे।

सांख्यिकी की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं तुलनीयता अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर के सांख्यिकीय उत्पादों जैसे जीएसओपी/जीडीडीपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मूल्य सूचकांक आदि की राष्ट्रीय मानकों, समयबद्धता एवं नैतिकता प्रासंगिकता के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। साथ ही राज्य स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों में अंतराल ओवरलैप या दोहराव को पहचान कर सुधारात्मक उपाय सुझाना तथा आधुनिक एवं आर्टी-समक्ष सांख्यिकीय विधियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना एवं उनकी निगरानी जैसे कार्यों का संपादन करेगी।

डेटा प्रसार, उपयोगकर्ता सहभागिता एवं नैतिक प्रासंगिकता अंतर्गत राज्य सांख्यिकीय उत्पादों का समय पर प्रसार सुनिश्चित करना तथा एम.ओ.एस.पी.आई के राष्ट्रीय डेटा प्रसार मानकों अग्रिम रिलीज कैलेंडर एवं मेटाडेटा सहित अनुरूप सुगम बनाना, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं, राज्य प्राथमिकताओं एवं उभरते क्षेत्रों पर एम.ओ.एस.पी.आई को फीडबैक प्रदान करना तथा साक्ष्य-आधारित नैतिक निर्माण, कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन में सांख्यिकी के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का संपादन करेगी।

क्षमता निर्माण एवं संस्थागत सुदृढीकरण अंतर्गत एम.ओ.एस.पी.आई के अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग के सहयोग से राज्य एवं जिला सांख्यिकी संवर्ग की क्षमता का विकास, संस्थागत सुदृढीकरण के लिए सुझाव जैसे सांख्यिकीय संवर्ग की स्थापना, डीईएस का अध्ययन, सर्वेक्षण एवं आर्टी संसाधनों में सुधार तथा राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने जैसे कार्यों का संपादन करेगी।

नर्मदा के चौथे चरण के लिए इंदौर निगम जारी करेगा ब्लू बांड



इंदौर। शहर की पेयजल व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इंदौर निगम ने नर्मदा चौथे चरण परियोजना के तहत ब्लू बांड जारी करने का फैसला किया है। करीब 1600 करोड़

रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना में एक हजार करोड़ रुपये की राशि जनता की भागीदारी से बांड के माध्यम से जुटाई जाएगी।

नगर निगम इससे पहले सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी पब्लिक इश्यू जारी कर चुका है। उस परियोजना के तहत स्थापित 60 मेगावाट सोलर पार्क से निगम को हर महीने करीब 5 करोड़ रुपये

की बचत हो रही है। इसी सफलता को देखते हुए अब जल क्षेत्र की बड़ी परियोजना के लिए भी बांड मॉडल अपनाया जा रहा है। महापौर पुष्पभित्र भागवत ने बताया कि परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये बैंक ऋण से और 1000 करोड़ रुपये

ब्लू बांड के माध्यम से जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत निगम को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्राप्त होगी। नगर निगम का दावा है कि इस परियोजना से भविष्य की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और शहर के विकास कार्यों में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

चार दिन बाद मथुरा में मिला भोपाल का लापता अंश

ट्रेन में अकेले बैठकर पहुंचा था मथुरा, सीसीटीवी से मिला सुराग

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल से चार दिन पहले लापता हुआ 6 वर्षीय अंश मैना मथुरा में सुरक्षित मिल गया है। भोपाल पुलिस की छह टीमों लगातार बच्चे की तलाश में जुटी थीं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने अंश को ट्रेस किया। अंश को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। टीम जल्द ही उसे मथुरा से भोपाल लेकर खाना होगी।

जानकारी के अनुसार अंश मैना इंदगाह हिल्स स्थित बाजपेयी नगर मल्टी का रहने वाला है। उसकी मां लालघाटी स्थित मल्टी केयर अस्पताल में भर्ती थीं। मंगलवार को अस्पताल परिसर के पास खेलते समय अंश अचानक गायब हो गया था। अनहोनी की आशंका चलते पुलिस ने अंश के लापता होने के बाद घटना स्थल के आसपास सर्चिंग की थी।



पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बच्चे की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों बनाई गईं और शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। एसीपी अनिल बाजपेयी के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अंश एक ट्रेन में अकेले बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टूट और अन्य तकनीकी माध्यमों से उसकी तलाश तेज कर दी। आखिरकार चार दिन बाद अंश मथुरा में मिल गया। पुलिस अब बच्चे से बातचीत कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह मथुरा तक कैसे पहुंचा।

सीसीटीवी बना सबसे बड़ा सुराग

अंश की तलाश में पुलिस ने शहरभर के कैमरों की जांच की। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में अंश अकेले ट्रेन में बैठा हुआ नजर आया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने रेलवे मार्ग को खंगालना शुरू किया और बच्चे की लोकेशन मथुरा तक पहुंची।

छह टीमों चार दिन तक करती रहीं तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने छह टीमों लगाई थीं। पुलिस लगातार रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के जरिए बच्चे को खोज रही थी। आखिरकार टीम को सफलता मिली और अंश को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

भोपाल। ज्ञानतीर्थ सप्रे संग्रहालय की ज्ञान संपदा में एक नया आयाम तब जुड़ा जब सुप्रसिद्ध इतिहासविद् और मप्र राज्य गजेटियर एवं अभिलेखागार के पूर्व संचालक शंभुदयाल गुरु का बेशकीमती खजाना संग्रहालय की धरोहर में शामिल हुआ। स्व. गुरु की यह विशाल सामग्री उनके परिजनों ने संग्रहालय को सौंपी है। यह विरासत यहां का हिस्सा बनने के बाद संग्रहालय में 'शंभुदयाल गुरु इतिहास प्रभाग' की स्थापना की गई है।

इस नवीन प्रभाग का लोकार्पण संग्रहालय के 43 वें स्थापना दिवस 19 जून को हुआ। इस अवसर पर प्रदेश की पांच विभूतियों को 'कर्मवीर सम्मान' से सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मानस भवन के अध्यक्ष सांसद श्री रघुनंदन शर्मा ने कहा कि स्व. शंभुदयाल गुरु ने इतिहास के क्षेत्र में जो किया वह अपने आप में अनूठे हैं। शर्मा ने गुरु जी की ज्ञान संपदा सप्रे संग्रहालय को सौंपने के लिए गुरु परिवार के प्रति आभार भी प्रकट किया।

आरंभ में स्वागत वक्तव्य देते हुए संग्रहालय के संस्थापक निदेशक विजयदत्त श्रीधर ने स्व. गुरु जी की पत्नी श्रीमती कमलेश गुरु ने जो यह खजाना सौंपा है इससे संग्रहालय की संपदा में और इजाफा हुआ। इसके लिए उन्होंने गुरु जी की चारों बेटियों के प्रति भी आभार माना। उन्होंने बताया कि आज यहां पांच करोड़



पत्ने,पौने दो लाख किताबें, दस हजार पत्र, पच्चीस-तीस हजार पत्रिकायें उपलब्ध हैं।

इस अवसर पर अशोक मनवानी कृत मोनोग्राफ 'बेजोड़कलमकार राजकुमार' तथा 'दूर और नजदीक से सरोज गुप्ता' का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में सप्रे संग्रहालय के परिकल्पनाकार विजयदत्त श्रीधर को डीटिड की मानद उपाधि मिलने पर संग्रहालय के अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार अवस्थी और मार्गदर्शक प्रो. रवेश ने उनका अभिनंदन किया। आभार प्रदर्शन शोध विशेषज्ञ डॉ. अल्पना गिरी ने किया। इस अवसर पर कर्मवीर सम्मान से सम्मानित विशिष्ट जनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सुभाष अत्रे ने दादा माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र कर्मवीर और दादा से अपने जुड़ाव का स्मरण भी

किया। कवि-कथाकार संतोष चौबे ने कहा कि मूलतः मैं, विज्ञान से जुड़ा रहा लेकिन जब यह देखा कि विज्ञान की अपेक्षा साहित्य समाज को जोड़ने और सरस बनाने में कारगर है तो इस तरफ उन्मुख हुआ और कविता, कहानी और उन्मत्स्य लगभग हर विधा में लेखन किया। संस्कृतसेवी श्रीराम तिवारी ने कहा कि मैं हमेशा से ही संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आंचलिक पत्रकार नूरूल हसन नूर ने कहा कि भारत ने हिंदी को अपनाया जरूर पर उसे अनिवार्य नहीं किया। इसी का परिणाम है कि भारत आज भी अखंड है और रहेगा। यह हिंदी की सामर्थ्य का प्रमाण है। हिन्दी सेवी डॉ. जवाहर कर्नावट ने कहा कि आज मिला यह सम्मान घरमें मिला सम्मान है। इसलिए यह मेरे लिए गौरव की बात है।